सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
YouTube
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 90, नई दिल्ली, गुरुवार, 27 जनवरी 2023, पेज 8

NEWS NTV TRANSPORT VISHESH
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 एलजी के बुलावे पर केजरीवाल का जवाब, कहा- मैं पंजाब जा रहा
05 ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है भारत
08 गणतंत्र दिवस परेड इस बार क्यों खास और अलग

आज का सुविचार

हर दिन अच्छा हो ये जरुरी नही होता. पर हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरुर होता है.

इंफ्रा सेक्टर के लिए बजट में बढ़ेगा आवंटन! रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट-हाइवेज पर होगा फोकस

सूत्रों ने दावा किया कि इस बजट में एनएचएआई को करीब 20 से 30 फीसदी ज्यादा फंड आवंटित किए जाने की संभावना है

संजय बाटला

देश में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विकास पर सरकार के बढ़ते फोकस के साथ आगामी बजट में सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को बजटीय सहायता मिलने की संभावना है, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 20 फीसदी अधिक हो सकती है.

नई दिल्ली। सूत्रों ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए आगामी बजट में 2.20 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक की सीमा में सकल बजटीय समर्थन की संभावना है. पिछले बजट (वित्त वर्ष 2022-23) में केंद्र ने सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में लगभग 1.99 लाख करोड़ रुपये रखे गए थे. सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के लिए केंद्र के बजटीय आवंटन के बारे में सरकारी आंकड़ों ने मंत्रालय को बढ़ते आवंटन की प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है, जो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार और सुधार को दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है.

जानें पिछले बजट का रिपोर्ट कार्ड

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2017-18 में केंद्र का बजटीय आवंटन 59,636 करोड़ रुपये था और इसने साल दर साल काफी उछाल दर्ज किया, जो 2022-23 में 1,99,108 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान 12,200 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा था. नवंबर, 2022 तक 4,766 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है.

निर्माण लागत भी बढ़ी हैं

अधिकारियों ने कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण निर्माण की गति प्रभावित हुई और मंत्रालय मार्च 2023 तक 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का लक्ष्य पूरा कर सकता है. उन्होंने कहा कि बढ़ते ब्याज खर्च और बढ़ती भूमि अधिग्रहण लागत के बीच मंत्रालय को लक्ष्य पूरा करने में मदद करने के लिए आगामी बजट में उच्च बजटीय आवंटन आवश्यक है. इसके अलावा ईंधन की बढ़ती लागत के कारण पिछले कुछ महीनों में निर्माण की लागत भी काफी बढ़ गई है और ये सभी कारक अधिक आवंटन की मांग करते हैं.

NHAI को मिलेगा ज्यादा फंड

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएसएआई) राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार राजमार्ग निर्माण एजेंसी को 2022-23 में 1,34,015 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान से 100 फीसदी अधिक है. सूत्रों ने दावा किया कि इस बजट में एनएचएआई को करीब 20 से 30 फीसदी ज्यादा फंड आवंटित किए जाने की संभावना है. एनएचएआई के व्यय में अंब्रेला हाईवे योजना, भारतमाला परियोजना, सड़कों और पुलों के निर्माण और कुछ अन्य घटकों के लिए धन शामिल है.

नई सड़कों के लिए ज्यादा पैसा आएगा

सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क अवसंरचना योजना भारतमाला परियोजना चरण- वन में लगभग 24,800 किलोमीटर एनएच नेटवर्क का विकास शामिल है जैसे कि आर्थिक गलियारे, इंटर-कॉरिडोर और फीडर सड़कें, राष्ट्रीय गलियारे दक्षता में सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें, एक्सप्रेसवे साथ ही शेष एनएचडीपी के तहत 10,000 किमी सड़कें.

भारतमाला परियोजना पर जोर

देश में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विकास के अलावा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को रसद दक्षता की सुविधा प्रदान करते हैं, 35 बहु मॉडल रसद पार्क (एमएमएलपी) विकसित किए जाने हैं. ये प्रमुख कार्गो समेकन और वितरण हब के रूप में कार्य करेंगे. सूत्रों ने कहा कि देश में 35 एमएमएलपी के साथ भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन से रसद दक्षता में और वृद्धि होने की उम्मीद है.

बजट से पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार की उम्मीद

अधिकारियों ने कहा कि आगामी बजट से पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार की उम्मीद है. भारतमाला परियोजना चरण-1 को 5.35 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 34,800 किलोमीटर की लंबाई के लिए मंजूरी दी गई थी. दिसंबर 2022 तक, लगभग 23,500 किलोमीटर के लिए काम दिया गया था और लगभग 11,400 किलोमीटर लंबाई का निर्माण किया जा चुका था. बाकी परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है. सड़कों और पुलों के तहत होने वाले खर्च में एनएच का विकास, एक्सप्रेसवे से संबंधित परियोजनाएं, विभिन्न परियोजनाओं के तहत गलियों की संख्या में वृद्धि और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विकास शामिल है. 2022-23 में सड़कों और पुलों के लिए आवंटन 64,573 करोड़ रुपये आवंटित है.

इनसाइड

नंगल से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वोल्वो बस शुरू, 1100 रुपये लगेगा किराया

ऊना। पंजाब के परिवहन मंत्री ने लालजीत सिंह भुल्लर और शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को नंगल से दिल्ली के लिए वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाई। बस नंगल से दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के लिए चलेगी। बस में पहली बार सफर करने वाले जरनैल सिंह, राजी खन्ना, सुनील कुमार, शमशेर सिंह, राज कुमार, नीलम कुमार और रेनू ने कहा कि बस के चलने से विदेश जाने और विदेश से आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। अगर टैक्सी कर नंगल से दिल्ली एयरपोर्ट जाना हो तो करीब आठ हजार किराया लगता है। बस में मात्र 1100 रुपये किराया लगेगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के तहत बस नंगल में शुरू की गई है। बस दोपहर 01:30 बजे नंगल से चलेगी और रात 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगी। एयरपोर्ट से रात 11:40 बजे बस आईएसबीटी दिल्ली के लिए रवाना होगी। आईएसबीटी से रात 12:50 पर बस नंगल के लिए चलेगी और सुबह 7 बजे के करीब नंगल पहुंचेगी। नंगल से एयरपोर्ट तक का किराया 1100 रुपये होगा। बस नंगल से वाया आनंदपुर साहिब, रूपनगर और चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पंहुचेगी।

कागजों में बस दौड़ाने वाले संविदा चालक-परिचालक की सेवाएं समाप्त

एनटीवी संवाददाता

पीलीभीत। कागजों में 110 किलोमीटर तक रोडवेज बस दौड़ाने वाले संविदा चालक और परिचालक की सेवाएं समाप्त कर दी गईं हैं। एआरएम ने मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कराई थी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई है। स्थानीय डिपो से पांच जनवरी को रोडवेज बस संख्या यूपी 78 एफटी 9043 पीलीभीत से माधोटांडा होते हुए दिल्ली के आनंद विहार के लिए रवाना होना दिखाई गई थी। बस में दो चालक थे। बस के माधोटांडा, पूरनपुर, सेटेलाइट बस स्टैंड होते हुए आनंद विहार तक जाने व लौटने का रूट दिखाया गया है। मगर संविदा चालक राजकुमार, परिचालक देवेंद्र बस पीलीभीत से बरेली होते हुए आनंद विहार ले गए और इसी रूट से पीलीभीत ले आए। आते-जाते समय माधोटांडा नहीं गए। मामला संज्ञान में आने बाद एआरएम वीके गंगवार ने जांच कराई। जांच के दौरान संज्ञान में आया कि चालक और परिचालक दोनों ने गलत तरीके से 110 किलोमीटर बस चलना दिखाया है। जिससे निगम को राजस्व की हानि हुई है। एआरएम ने तीन दिन में चालक परिचालक से स्पष्टीकरण तलब किया था। स्पष्टीकरण में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस पर एआरएम ने चालक और परिचालक की संविदा समाप्त कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है।

बरेली में उतर गया था दूसरा चालक

पीलीभीत से दिल्ली के दो संविदा चालक राज कुमार, रावेंद्र पाल सिंह और परिचालक देवेंद्र कुमार बस को लेकर रवाना हुए थे। दिल्ली से लौटते समय रावेंद्रपाल, पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण बरेली में उतर गया। इससे चालक राजकुमार और परिचालक देवेंद्र कुमार के हस्ताक्षर से शीट डिपो में जमा हुई थी। इसलिए दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

दो चालक और एक परिचालक बस लेकर गए थे। मगर लौटते समय एक चालक बरेली में उतर गया था। शीट एक चालक और परिचालक ने जमा की। इसीलिए इन्हीं दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

-वीके गंगवार, एआरएम

एमडी संजय कुमार ने कहा, रोडवेज पर घाटे की मार, किराया बढ़ाने का चल रहा विचार

रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड में रोडवेज में 154 पैसे प्रति किमी प्रति सीट किराया है। महाराष्ट्र में ये 145 पैसे, हिमाचल में 140 तथा पंजाब में 122 पैसे प्रति किमी प्रति सीट तक किराया है। जबकि यूपी में किराया 105 पैसे प्रति सीट प्रति किमी ही है।

लखनऊ। उप्र परिवहन निगम पर पिछले 10 साल में पहली बार घाटे की मार पड़ रही है। पिछले तीन साल से किराया न बढ़ने और डीजल के दाम इस दौरान 26 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ने के कारण यह घाटा इस साल 210 करोड़ रुपये के पार चला गया है। ऐसे में रोडवेज किराया बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी कर रहा है।

रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड में रोडवेज में 154 पैसे प्रति किमी प्रति सीट किराया है। महाराष्ट्र में ये 145 पैसे, हिमाचल में 140 तथा पंजाब में 122 पैसे प्रति किमी प्रति सीट तक किराया है। जबकि यूपी में किराया 105 पैसे प्रति सीट प्रति किमी ही है। एक जनवरी 2020 से यूपी में किराया भी नहीं बढ़ा है, ऐसे में रोडवेज को प्रतिमाह 52 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हो रहा है। स्पेयर पार्ट की कीमत में भी वृद्धि हो चुकी है।

एमडी रोडवेज संजय कुमार ने बताया कि इस पर मंथन हो रहा है कि रोडवेज को घाटा भी न हो और यात्रियों पर भी बोझ न पड़े। इसके लिए हितधारकों से भी सुझाव मांगे गए हैं। मालूम रहे कि प्रदेश में रोडवेज की 11,200 बसें चल रही हैं। इनमें प्रतिदिन 15-16 लाख यात्री सफर करते हैं। इनसे प्रतिदिन लगभग 12 करोड़ रुपये की आय हो रही है। ज्यादा ठंड होने या सहालग न होने पर यह आय काफी कम हो जाती है, जबकि खर्च प्रतिदिन लगभग 14 करोड़ रुपये है। यहां 16 हजार स्थायी तथा 30 हजार अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं।

स्क्रैप वाहन पॉलिसी अधिसूचित, नया वाहन खरीदने पर मिलेगी इतनी छूट

एनटीवी संवाददाता

चंडीगढ़। जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर व्हीकल टैक्स में ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 15 प्रतिशत और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। पंजाब सरकार ने राज्य में प्रदूषण को घटाने के मकसद से स्क्रैप वाहन के मालिक को नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने संबंधी बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन संबंधी लागू की गई स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में पंजाब कैबिनेट द्वारा पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 की धारा 13 (3) के अधीन नई गाड़ियों की खरीद पर छूट देने का फैसला किया था।

जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर व्हीकल टैक्स में ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 15 प्रतिशत और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण-पक्षीय फैसले से स्क्रैपिंग पॉलिसी के अधीन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से आठ साल तक और नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक 15 साल तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस नीति के अंतर्गत जिस समय गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा तो इसे लेकर स्क्रैपर द्वारा ही गाड़ी की खरीद की जाएगी। इसके उपरांत स्क्रैपर द्वारा वाहन के मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (वाहन जमा करवाने का सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट गाड़ी के मालिक द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करवाने पर नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी। मंत्री ने बताया कि ट्रांसपोर्ट वाहन को रजिस्ट्रेशन से आठ साल तक स्क्रैप करना वैकल्पिक है।

निगम पार्षद पुष्पा सुरेंद्र सोलंकी को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया

74वें गणतंत्र पर झंडा रोहण एवं वसंत उत्सव

एस.ठी सेठी

एनटीवी, नई दिल्ली। विजय विहार रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन, रोहिणी के बैनर तले 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय निगम पार्षद पुष्पा सुरेंद्र सोलंकी द्वारा सेक्टर 1 रोहिणी, एमसीडी के महादेव पार्क में झंडा रोहण किया गया। इस मौके पर वसंत उत्सव के तहत महिलाओ ने सरस्वती वंदना के साथ-साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुती से सैंकडों की संख्या में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इससे पहले निगम पार्षद पुष्पा सुरेंद्र सोलंकी को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वालों में आरडब्ल्यूए के जनरल सैक्टरी एसडी सेठी, अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज, विनोद पराशर, राजेश साँवरिया, पं.मुरारी भारद्वाज, चक्रेश मित्तल, राकेश गोयल, बालम सिंह रावत, मंजू बंसल, रेनू मित्तल, मालती, मंजू सेठी, सरोज शर्मा प्रमुख थे।

इस अवसर पर निगम पार्षद के सामने महादेव पार्क की नष्ट होती हरियाली व जानलेवा बेतरतीब लटके पेडों की छंटाई करवाने का मसला उठाया। इस पर पार्षद पुष्पा सुरेंद्र सौलंकी ने पार्क समेत क्षेत्र की तमाम समस्याओ को जल्द ही दूर करने का आश्वासन भी दिया।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

सर्दियों में महिलाएं इन एसेसरीज से पाएं गजब का लुक, हर कोई करेगा तारीफ

सर्दियों के मौसम में बेस्ट लुक पाना कई लोगों के लिए मुश्किल टास्क साबित होता है. लेटेस्ट ड्रेसिंग सेंस फॉलो करने से लेकर ट्रेंडी विंटर वियर कैरी करने के बाद भी कुछ लोगों का लुक नॉर्मल नजर आता है. सर्दियों में सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए ज्यादातर लोगों का फोकस ड्रेस और मेकअप पर होता है. ट्रेंडी और डिफरेंट लुक पाने के लिए बेस्ट ड्रेस के साथ परफेक्ट मेकअप लुक कैरी करना काफी नहीं होता है. आपको बताने जा रहे हैं विंटर की कुछ कॉमन एसेसरीज, जिन्हें ट्राई करके आप अपने लुक को चुटकियों में एन्हान्स कर सकती हैं.

बैरेट कैप पहनें

सर्दियों में स्टाइलिश ड्रेस के साथ बैरेट कैप पहनकर आप डिफरेंट और ट्रेंडी लुक हासिल कर सकती हैं. वहीं सर्दियों के दौरान बैरेट कैप मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहते हैं. ऐसे में जींस, पैंट और स्कर्ट के साथ बैरेट कैप लगाकर अपने आउटफिट को फ्रेंच लुक दे सकती हैं.

ईयर मफ ट्राई करें

सर्दियों में कानों को ठंड से बचाने के लिए महिलाएं अक्सर स्कार्फ और मफलर का इस्तेमाल करती हैं. मगर सर्दी में ईयर मफ से कानों को कवर करना भी आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. इससे न सिर्फ आप कानों को ठंड से बचा सकती हैं बल्कि अपने लुक को भी स्टाइलिश बना सकती हैं. वहीं डिफरेंट लुक पाने के लिए आप मार्केट से कलरफुल और बेस्ट डिजाइन वाले ईयर मफ का चुनाव कर सकती हैं.

बेस्ट होगा बूट्स का चुनाव

सर्दी के मौसम में महिलाएं अमूमन शूज पहनना पसंद करती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो सर्दियों मे बूट्स ट्राई करके भी अपने लुक को एन्हॉन्स कर सकती हैं. खासकर सर्दियों में लेदर के बूट्स आपकी ब्यूटी में चार चांद लगाने का काम करते हैं. वहीं बूट्स में असहज महसूस करने पर फ्लीस बूट्स कैरी करना भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

स्कार्फ कैरी करें

सर्दियों में स्कॉर्फ का इस्तेमाल भी महिलाओं के लिए बेस्ट हो सकता है. सर्दियों में हर ड्रेस के साथ सिंपल, सोवर, और प्रंटेड वुलन स्कार्फ कैरी करके आप न सिर्फ ठंड से खुद का बचाव कर सकती हैं बल्कि फैशनेबल और ट्रेंडी लुक भी आसानी से हासिल कर सकती हैं.

महिलाएं विंटर ब्ल्यू से इस तरह खुद को उबारें, निराशा और उदासी से मिलेगी निजात

विंटर के मौसम में उदासी, निराशा और डिप्रेशन की शिकायत काफी महिलाओं को परेशान करती है. खासतौर पर अगर वे हाउस वाइफ या उम्रदराज महिला हैं तो विंटर ब्लूज़ के कई लक्षण उन्हें घर पर उदास महसूस कराते हैं. एवरीडेहेल्ड के मुताबिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के विशेषज्ञ यह मानते रहे हैं कि विंटर ब्लूज़ काफी कॉमन समस्या है जिसमें सामान्य से अधिक उदासी, कम ऊर्जावान या किसी भी चीज में मन ना लगने जैसे लक्षण दिखते हैं. शिकागो में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी फीनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर जैकलिन गोलन का कहना है यह एक संकेत है कि जो बताता है कि उन्हें अब जीवन में खुद पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं.

शुरू करना है खुद का बिजनेस, इन 8 ज़रूरी बातों को रखें याद

यदि आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने टार्गेट ऑडियंस को ध्यान में रखना होगा. साथ ही शुरुआत में पैसों के इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग आदि पर भी ध्यान देना होगा, तभी आप एक सक्सेफुल बिजनेस वूमने बन सकेंगी.

आज महिलाएं अपना नाम हर फील्ड में बना रही हैं. कुछ ऑफिस में काम करती हैं, तो कुछ अपना बिजनेस कर रही हैं और उसमें सफलता हासिल कर रही हैं. अक्सर कुछ महिलाएं शादी इसलिए भी देर से करती हैं कि वे एक कामयाब वर्किंग वूमन बन जाएं. कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, जो शादी के बाद घर चलाने के साथ ही कुछ काम भी करना चाहती हैं. खुद का बिजनेस करना चाहती हैं. यदि आपकी भी शादी हो गई है और आपका कुछ सपना था बनने का, किसी तरह का बिजनेस करने का तो अब भी देर नहीं हुआ है. आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं. यदि आप ऑफिस जाकर 9 घंटे की शिफ्ट नहीं करना चाहती हैं तो आप घर से कोई काम कर सकती हैं. हालांकि, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी रखना होगा, ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफल हो सकें.

कौन-कौस सा बिजनेस कर सकती हैं

आप यदि अपना बिजनेस करना चाहती हैं तो आप वही काम करें जिसमें आपने पढ़ाई की या कोई डिग्री ली हो. कई बार शादी हो जाने के बाद महिलाएं आगे पढ़ाई या करियर नहीं बना पाती हैं. ऐसे में महिलाओं के लिए अपना फैशन बुटीक खोलना, सिलाई-कढ़ाई का काम करना, इंटीरियर डिजाइनिंग, टिफिन सर्विस, होम ट्यूशन, एफिलिएट मार्केटिंग, डांस क्लास, रेडीमेड गार्मेंट बेचना, खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना, केक मेकिंग बिजनेस, पैकिंग बिजनेस, अचार या पापड़ बनाने का काम आदि कई ऐसे काम हैं, जो आप घर बैठे कर सकती हैं और बेहतर कमाई कर सकती हैं.

बिजनेस की शुरुआत करने से पहले रखें इन 8 बातों का ध्यान

-बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, इसमें सफलता पाना आसान नहीं. यह एक दिन का काम नहीं कि आज बिजनेस की शुरुआत की और कल से ही कमाई होने लगे. इसके लिए आपको धैर्य, लगन, मेहनत, हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा.

यदि आप अपनी मन-पसंद का कोई भी बिजनेस करना चाहती हैं तो पहले किसी सफल बिजनेस वूमेन के बारे में पढ़ें, जानें कि उन्होंने किस प्लानिंग के तहत इसकी शुरुआत की थी.

-यदि आपकी कोई दोस्त या घर-परिवार में किसी ने भी अपना बिजनेस शुरू किया है तो उससे पहले बात करें. यह जानने की कोशिश करें कि आज की डेट में किस काम में हाथ लगाना आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है. कई बार अपना बिजनेश शुरू तो लोग कर देते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक बरकरार रख पाना काफी चुनौती भरा काम होता है.

-किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले रिसर्च करना जरूरी है. यदि आप बिना रिसर्च किए कुछ भी काम शुरू करती हैं तो सफल होने की संभावना कम हो जाती है. जल्दबाजी में कोई काम ना करें शुरू. रिसर्च करने से जान पाएंगी कि आप अपने प्रोडक्ट, काम को मार्केट में कितने समय के लिए एक्टिव रख सकेंगी.

-किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए लोकेशन या स्थान भी मायने रखता है. यदि आप लोगों की पहुंच से दूर अपना ऑफिस सेटअप करती हैं या बिजनेस की शुरुआत करती हैं तो आप अपने टार्गेट कस्टमर की संख्या को बढ़ाने में नाकामयाब हो सकती हैं. बिजनेस के लिए ऐसा लोकेशन चुनें, जहां ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती रहे.

-किसी भी काम को शुरू करने से पहले पूंजी बेहद मायने रखती है. व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप कहां से कैपिटल को मैनेज करेंगी, इस पर सबसे पहले बात-विचार करें. यदि आप लोन लेंगी तो इसके लिए भी किसी एक्सपर्ट से राय जरूर ले लें. आप कब, किस तरह से लोन के पैसे चुकाएंगी इसकी प्लानिंग बेहद जरूरी है.

-यदि आप खुद की सेविंग्स से बिजनेस की शुरुआत करने वाली हैं तो पहले बिजनेस के नेचर को समझें. शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा लगा देना समझदारी नहीं होगी. इससे आपका व्यवसाय सफल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं. ऐसे में सोच-समझकर ही चीजों पर इनवेस्ट करें. स्टेप बाई स्टेप पैसे खर्च करें. एक्सपर्ट की राय लेना भी जरूरी है.

-आप हाउस वाइफ हैं और अपना काम शुरू कर रही हैं तो इसके लिए आपको बिजनेस में अपना समय भी देना होगा. खासकर, शुरुआत के एक साल आपके लिए चुनौतियों भरा हो सकता है. इसके लिए बिना धैर्य खोए अपनी सारी ऊर्जा लगाते हुए टाइम मैनेज करना भी आना होगा, ताकि आप घर और अपने काम को सही तरीके से संभाल सकें.

-व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आपकी मार्केटिंग भी जबरदस्त होनी चाहिए. इसके लिए कुछ पैसा मार्केटिंग पर भी आपको खर्च करना पड़ सकता है. आप जितना शुरुआत में अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगी, लोगों तक यह उतना ही पहुंचेगा. किसी भी काम को प्रमोट या मार्केटिंग किए बिना उसे आज के दौर में सफल बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है. आप जो काम शुरू करने जा रही हैं, वो काम पहले से ही यदि दस लोग कर रहे हैं तो आपको खुद को सफल बनाने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग, प्रमोशन, टेक्निकल स्किल, इन्वेस्टमेंट स्किल, पेशेंस, लगन, मेहनत आदि की बेहद जरूरत पड़ेगी. तभी आप बन सकती हैं एक सफल बिजनेस वूमन.

महिलाएं इन तरीकों से बढ़ाएं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी को ऐसे करें दूर

कहावत है कि अगर आपको खुद पर भरोसा है तो समझिए आपने आधा युद्ध पहले ही जीत लिया है. जी हां, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आप अपने अंदर की ताकत को पहचानती हैं और हर हालात में खुद पर भरोसा रखती हैं तो आपकी ये ताकत हर काम को आसान बना देने का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है. ये आत्मविश्वास ही है कि आप हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहती हैं और गलतियों से डरने की बजाय, सीख लेना पसंद करती हैं. ऐसे में अगर आप महसूस कर रही हैं कि आपके अंदर का आत्मविश्वास कहीं गायब हो गया है और आप खुद के प्रति सकारात्मक महसूस नहीं कर पाती हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं.

महिलाएं इस तरह बढ़ाएं अपना आत्मविश्वास

गलतियों से सीखें- इंसान होने के नाते गलतियां करना आपका अधिकार है. हर इंसान गलतियों से ही सीखता है. ऐसे में अगर आप गलतियों से डरती हैं तो इस डर को अपने बाहर निकाल फेंकिए. क्योंकि आप इंसान हैं, भगवान नहीं.

नकारात्मक विचारों को रोकें- अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं या कुछ नकारात्मक बातें आपको परेशान कर रही हैं तो खुद को ऐसा करने से तुरंत रोकें. यह सोचें कि आपकी सोच ही आपको और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती या कम करती है. खुद को सकारात्मक सोच के लिए हमेशा मोटिवेट करें.

ना कहने से डर कैसा- कई महिलाओं को ना करने में दिक्कत होती है. ऐसे में वे ऐसे काम भी करने लगती हैं जिसे वे बिलकुल करना पसंद नहीं करतीं. आपको बता दें कि ना कहने का मतलब किसी का अपमान करना नहीं होता, और ना ही इंप्रेशन बनाने के लिए ना कहना जरूरी होता है.

कभी कभी 'स्टॉप' कहना जरूरी- अगर कोई आपके सामने लगातार आपको यह बोल रहा है कि आप कितनी बुरी दिखती हैं, या आपको परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है या तुम कुछ नहीं कर सकती आदि, तो उन्हें स्टॉप करना सीखें. अगर बोलने में असुविधा है तो आप ऐसी बातों पर हंस दें और ऐसी बातों को सकारात्मक रूप में लेते हुए खुद को बेहतर बनाने का बहाना बनाएं.

खुद को स्वीकारें- आप जैसी हैं अच्छी हैं. इस बात को खुद से बोलें. आप मोटी हैं, पतली हैं या दिखने में बेहद खूबसूरत नहीं हैं. ये बातें आपकी पूर्णता को नहीं बताते. आप जो हैं वो अपने काम से हैं, अपने बातचीत के तरीके से हैं, अपने व्यवहार और अपने आत्मविश्वास से हैं. खुद को खुद की तरह स्वीकारें और सकारात्मक रहें.

ऑफिस के बाद करनी है पार्टी, वर्किंग वूमन पर्स में रखें 6 मेकअप प्रोडक्ट

कई बार ऑफिस के बाद महिलाओं को पार्टी में जाना पड़ता है. लेकिन घर जाकर तैयार होने का समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में वर्किंग वूमन के लिए कुछ एसेंशियल मेकअप प्रोडक्ट्स को अपने हैंड बैग में कैरी करना बहुत जरूरी हो जाता है.

ऑफिस गोइंग वूमन आमतौर पर प्रोफेशनल आउटफिट कैरी करना पसंद करती हैं. वहीं ऑफिस जाते समय ज्यादातर महिलाएं लाइट मेकअप (Makeup tips) को तवज्जो देती नजर आती हैं. हालांकि ऑफिस के बाद महिलाओं को कई बार पार्टी में भी जाना पड़ सकता है. ऐसे में वर्किंग वूमन अपने पर्स में 6 मेकअप एसेंशियल कैरी करके पार्टी के लिए मिनटों में परफेक्ट लुक हासिल कर सकती हैं.

कई बार महिलाओं को ऑफिस के बाद घर जाने का समय नहीं मिल पाता है. जिसके चलते वर्किंग वूमन को प्रोफेशनल मेकअप लुक के साथ ही पार्टी में जाना पड़ता है. वहीं पूरी मेकअप किट को ऑफिस ले जाना भी महिलाओं के लिए संभव नहीं हो पाता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ एसेंशियल मेकअप प्रोडक्ट्स के नाम, जिन्हें अपने हैंड बैग में कैरी करके आप आसानी से पार्टी के लिए रेडी हो सकती हैं.

फाउंडेशन का इस्तेमाल करें

फाउंडेशन का इस्तेमाल मेकअप को बेस प्रोवाइड करने का काम करता है. ऐसे में सबसे पहले फेस वॉश करके चेहरे को टिशू पेपर से पोंछ लें. अब फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करें. वहीं अपनी स्किन टाइप के अनुसार फाउंडेशन का चुनाव करना बेस्ट रहता है.

कंसीलर की मदद लें

कंसीलर चेहरे के दाग-धब्बों को छुपाकर मेकअप को फिनिशिंग लुक देने में मददगार होता है. ऐसे में कंसीलर को ट्राइंगल शेप में लगाते हुए हल्का-हल्का फैलाएं. इसके बाद चेहरे पर ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई करें. इससे आपका चेहरा ग्लोइंग नजर आएगा.

आइलाइनर अप्लाई करें

बेस्ट मेकअप लुक कैरी करने के लिए आई मेकअप पर ध्यान देना भी जरूरी होता है. ऐसे में आंखों पर आइलाइनर लगाने के लिए व्हाइट पेंसिल का इस्तेमाल करना भी अच्छा ऑप्शन होता है. साथ ही आंखों की वॉटर लाइन पर आइलाइनर लगाकर आप आसानी से अपने लुक को एन्हॉन्स कर सकती हैं.

काजल लगाएं

काजल को आई मेकअप का एसेंशियल पार्ट माना जाता है. वहीं काजल का इस्तेमाल आंखों को हाइलाइट करने के साथ-साथ चेहरे की सुंदरता निखारने में भी मददगार होता है. ऐसे में आइलाइनर लगाने के बाद आंखों पर काजल लगाना न भूलें.

फेस पाउडर से दें टचअप

फेस पाउडर का इस्तेमाल करके आप मेकअप को फाइनल टचअप दे सकती हैं. ऐसे में स्किन टोन के अनुसार फेस पाउडर के शेड्स का चुनाव करें. इससे आपका चेहरा निखरा और चमकदार दिखने लगेगा.

लिपस्टिक यूज करें

कंप्लीट मेंकअप लुक कैरी करने के लिए लास्ट में लिपस्टिक लगाना न भूलें. इसके लिए होंठो पर लिपस्टिक लगाएं. अब दोनों लिप्स के बीच में टिशु पेपर लगाकर होंठो को आपस में प्रेस करें. इसके बाद होंठो पर दोबारा लिपस्टिक अप्लाई करें. इससे आपका लिप कलर लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा.

इनसाइड

वंचित व उपेक्षित परिवारों की 100 कन्याओं का सामूहिक विवाह, सेवा भारती ने किया कार्यक्रम का आयोजन

दिल्ली। अट्ठारह स्थानों पर हुए इन विवाह समारोह में इन सभी बातों की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ी। साथ ही उन्होंने सेवा कार्य कर रहे सभी कार्यकर्ताओं व परिवारों का आभार जताया जो सेवा भारती के इस अभियान का हिस्सा बने। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा भारती समाज के उन सहयोगी व दानदाताओं का विशेष आभार प्रकट करती है जिनके योगदान से आज का यह आयोजन सफल बना। यदा कदा होने वाले सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रमों में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है । समाज के कमजोर वर्गो के बीच काम कर रही सेवा भारती एक ओर जहां उपेक्षित वर्ग के सामाजिक उत्थान के प्रति निरंतर प्रगतिशील है तो दूसरी ओर इस समाज को अपने दम पर आत्मनिर्भर बनाने के सभी प्रयासों के बीच विशेष रूप से चलाये जा रहे सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रमों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जो हर वर्ष के वैवाहिक आवेदनों के साथ साथ आयोजन स्थलों की संख्या में लगभग दुगने से भी ज्यादा है। इसी क्रम में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एवं वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर दिल्ली में 18 अलग अलग स्थानों पर कुल 120 से अधिक सामुदायिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये गए। पिछले 20 वर्षों से सेवा भारती लगातार इस प्रकार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर रही है जिसमे 1700 से अधिक की संख्या में विवाह सम्पन्न हुए हैं। सेवा भारती दिल्ली के महामंत्री श्री सुशील गुप्ता के अनुसार ₹ जाति, भाषा, क्षेत्र, मत-संप्रदाय, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब आदि के नाम पर बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में पिरोने के छोटे से प्रयास का नाम ही सेवा भारती है। समाज में एक ओर जहाँ बड़ी मात्रा में वंचित-उपेक्षित वर्ग है, वहीं दूसरी ओर ज़िम्मेदार व संस्कारित संपन्न समाज भी है। इन दोनों के बीच की कड़ी का दूसरा नाम ही सेवा भारती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन व संस्कार के माध्यम से आज के सेवित जन आने वाले कल के सेवक बनें। सेवा भारती इसी उद्देश्य की पूर्ति में पिछले 43 वर्षों से प्रयासरत है। ये सामूहिक विवाह मात्र दो वंचित परिवारों के युवाओं का मिलन ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सकारात्मक सोच व वंचित समाज के लिये एक जुट होकर खड़े रहने की मिसाल को भी दर्शाता है। ये सामूहिक विवाह दर्शाते हैं कि सभी कार्य सरकार नहीं कर सकती और समाज के अपने कर्तव्य भी हैं और इसकी शक्ति भी असीमित है।

दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा: एलजी के बुलावे पर केजरीवाल का जवाब, कहा- मैं पंजाब जा रहा, किसी और समय मिलूंगा

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान के बीच गुरुवार को राजनिवास से बुलावे के बाद सीएम केजरीवाल ने किसी और समय मिलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि बुलावे के लिए धन्यवाद एलजी साहब। मैं कल पंजाब जा रहा हूं। माननीय उपराज्यपाल से हम मिलने के लिए किसी और समय का अनुरोध कर रहे हैं।

बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके मंत्रियों और आप के 10 विधायकों को मिलने बुलाया है। राजनिवास के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के किन्हीं 10 विधायकों के साथ शाम चार बजे बैठक में आने के लिए कहा गया है। प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को फिनलैंड में भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव सहित कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और एलजी आमने-सामने हैं।

वहीं इससे पहले विधानसभा सत्र में भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच खींचतान का सिलसिला चरम रहा था। 16 जनवरी दिन सोमवार को विधानसभा से लेकर सड़क तक सियासी हंगामा बरपा था। सदन की पहले दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार के कामकाज पर दखल देने का आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष के सदस्य भड़के थे। वहीं, विपक्ष प्रदूषण पर चर्चा न करवाने से नाराज आया था। दिल्ली सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरने के लिए भाजपा विधायक मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे। उनके इस कदम पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई और सिलिंडर बाहर करने के निर्देश दिए थे।

ऐसे में आलम यह रहा था कि एक घंटे में तीन बार सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को स्थगित करनी पड़ी थी, बावजूद इसके सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप विधायकों ने राजनिवास तक पैदल मार्च निकाला था।

आखिरकार LG ने CM केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को मिलने के लिए बुलाया; 10 विधायक भी साथ लाने को कहा

राजनिवास के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के किन्हीं 10 विधायकों के साथ शाम चार बजे बैठक में आने के लिए कहा गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच जारी खींचतान के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके मंत्रियों और आप के 10 विधायकों को मिलने बुलाया है। उन्होंने सभी को शुक्रवार शाम राजनिवास में आने के लिए कहा है। राजनिवास के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के किन्हीं 10 विधायकों के साथ शाम चार बजे बैठक में आने के लिए कहा गया है। बता दें कि प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को फिनलैंड में भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव सहित कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और एलजी आमने-सामने हैं।

16 जनवरी को केजरीवाल और उनकी पार्टी के विधायकों ने शिक्षक प्रशिक्षण प्रस्ताव को लेकर एलजी वीके सक्सेना से मिलने के लिए विधानसभा से राज निवास तक मार्च निकाला था। करीब एक घंटे के इंतजार के बाद सीएम केजरीवाल ने वहां से लौटते हुए दावा किया था कि एलजी ने उनसे और उनकी सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया व आप विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया।

इसके कुछ दिन बाद एलजी ने केजरीवाल को लिखे एक पत्र में दिल्ली सरकार के आरोपों से इनकार किया था, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने एक बैठक के लिए जोर दिया, जिसमें उनके सभी विधायक शामिल होंगे।

ऑटो ड्राइवर की चाकू गोदकर हत्या, पुलिस कर रही जांच

नई दिल्ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से शव कब्जे में ले लिया और हत्या की धारा में मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर-13 इलाके से एक ऑटो चालक के हत्या की खबर सामने आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें बीती रात 2.00 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल मिली कि एक ऑटो चालक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से शव कब्जे में ले लिया और हत्या की धारा में मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान 44 वर्षीय ऑटो चालक के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आाय है कि चालक की हत्या ऑटो में मौजूद दो लोगों ने की है। पुलिस हर एंगल से केस की जांच कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई टीम बनाई है।

लाल किला प्रागंण में भारत पर्व आज से, दिखेगी मिनी इंडिया की झलक, आयोजन 31 जनवरी तक

दिल्ली। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लाल किला प्रागंण में 26 जनवरी से छह दिवसीय कार्यक्रम "भारत पर्व" आयोजित करने जा रहा है। लाल किले के प्रागंण में 31 जनवरी तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को गणतंत्र दिवस परेड़ की सर्वश्रेष्ठ झाकियां देखने को भी मिलेंगी। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को इस वीक एंड पर मिनी भारत की झलक देखने और विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला और खान-पान से रूबरू होने का मौका मिलेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लाल किला प्रागंण में 26 जनवरी से छह दिवसीय कार्यक्रम "भारत पर्व" आयोजित करने जा रहा है। लाल किले के प्रागंण में 31 जनवरी तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को गणतंत्र दिवस परेड़ की सर्वश्रेष्ठ झाकियां देखने को भी मिलेंगी। खास बात यह है कि यहां दर्शकों को सरकार की जी 20, एक भारत-श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश, जनभागीदारी योजनाओं को जानने का मौका भी मिलेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक मंडलों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ मिलकर " भारत पर्व " नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जबकि जबकि पर्यटन मंत्रालय इसमें नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। यहां पर सांस्कृतिक प्रदर्शन, एक अखिल भारतीय फूड कोर्ट और 65 हस्तकला स्टालों के साथ एक अखिल भारतीय शिल्प बाजार भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। दर्शक सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक घूम सकते हैं।

बाजरा से तैयार खाना होगा खास

सरकार मोटे अनाज को आहार में शामिल करने के मकसद से प्रचार कर रही है। यहां पर दर्शकों को विभिन्न राज्यों में बाजरा से तैयार पकवान रखे जाएंगे। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

पहली बार कर्तव्य पथ पर निकली गणतंत्र दिवस परेड, महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दी सलामी

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर पहली बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड व झांकियां निकलीं। परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने ली। समारोह के विशेष अतिथि मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रहे।

कोरोना से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में करीब सवा लाख लोग शामिल होते थे, वहीं कोरोना के दौरान करीब 25 हजार लोग शामिल हुए। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड की खास बात यह रही कि परेड में शामिल थलसेना के सारे हथियार स्वदेशी थे।

परेड हर साल की तरह विजय पथ से लाल किले तक निकली। इस बार परेड में 45 हजार लोग शामिल हुए। इसके लिए करीब 12 हजार पास बांटे गए और करीब 32 टिकट ऑनलाइन बिके। इस बार दर्शकों के बैठने के लिए अलग तरह के इंतजाम थे।

वर्टिकल प्लेटफॉर्म पर कुर्सियां लगाई गईं थीं ताकि पीछे बैठे लोग भी आसानी से परेड देख सकें। कोरोना से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में करीब सवा लाख लोग शामिल होते थे, वहीं कोरोना के दौरान करीब 25 हजार लोग शामिल हुए। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड की खास बात यह रही कि परेड में शामिल थलसेना के सारे हथियार स्वदेशी थे।

परेड की शुरुआत 10.30 बजे से हुई जो करीब 90 मिनट चली

गणतंत्र दिवस की परेड

गणतंत्र दिवस की परेड - फोटो : जी पाल

10.06 समारोह की शुरुआत

राष्ट्रीय समर स्मारक पर पीएम मोदी ने राष्ट्र की ओर से शहीद सैनिकों को श्रदांजलि दी।

10.21 पीएम कर्तव्य पथ पर पहुंचे।

10.25 उपराष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर पहुंचे।

10.26 राष्ट्रपति के अंगरक्षक कर्तव्य पथ पर पहुंचे।

10.27 राष्ट्रपति के साथ आते हैं।

घुड़सवार अंगरक्षकों का यह रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठतम रेजिमेंट में से एक है। अपनी स्थापना के 250 साल पूरे हो गए हैं। इसके जवान छह फुट के होते हैं और अपने हाथों में करीब नौ फुट के लंबे भाले लिए होते हैं।

10.29 21 तोपों की सलामी

खास बात ये कि देश में बने 105 एमएम लाइट फील्ड गन से ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।

10.30 राष्ट्रपति के आगमन पर वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। इसके साथ राष्ट्रीय गान की धुन बजी।

गणतंत्र दिवस की परेड

10.31 आकाश में एमआई 17वीं 5 के चार हेलीकॉप्टर वाईन ग्लाल फॉरमेशन में थे। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेना के तीनों अंगों के ध्वज थे। इन हेलीकॉप्टरों ने दर्शकों पर फूलों की पंखुड़ियां भी बिखेरी।

10.31 परेड कमांडर

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ

दिल्ली एरिया के जीओसी

दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी*

10.32 परेड उपकमांडर

मेजर जनरल भवनीश कुमार

पैराशूट रेजिमेंट से कमीशन

10.34 परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता

बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान। युद्ध के दौरान आसाधारण वीरता का परिचय देते हुएअ जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को

सूबेदार मेजर बाना सिंह (रिटा)

सूबेदार मेजर योगेन्द्र सिंह (रिटा)

सूबेदार मेजर संजय कुमार

अशोक चक्र

असाधारण वीरता का प्रर्दशन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को

मेजर जनरल सीओ पिठावाला (रिटा)

लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार (रिटा)

लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम (रिटा)

गणतंत्र दिवस की परेड

गणतंत्र दिवस की परेड - फोटो : जी पाल

10.35 मिस्र की सेना संयुक्त बैंड एवं मार्चिंग दस्ता पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। 144 सैनिकों का दस्ता, जो मिस्र के प्रभुत्व और गौरव का प्रदर्शन करती है। मिस्र के लोगों ने दुनिया में पहला साम्राज्य स्थापित किया।

10.36 61 कैवलरी

विश्व में अपनी तरह की इकलौती सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट

आदर्श वाक्य- अश्व शक्ति यशोबल अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम

मैकेनाइज्ड दस्ते

10.37 एमबीटी अर्जुन

तीसरी पीढ़ी का देश में बना युद्धक टैंक।

120 एमएम की मुख्य राइफल गन

12.7 एमएम एंटी एयर क्राफ्ट मशीन गन

70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार

10.38 नाग मिसाइल सिस्टम (नामिस)

नाग मिसाइल सिस्टम एक टैंक विध्वंसक है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। एक व्हीकल में छह नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम हैं। इसकी रेंज 5 किलोमीटर है।

10.39 आईसीवीबीएमपी-2 (सारथ)

सारथ नाम का यह इंफ्रैट्री कॉम्बेट व्हीकल है जिसमें घातक हथियार होते हैं। खासकर इससे रात में युद्ध में घातक क्षमता और बढ़ जाती है। यह हर क्षेत्र में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। यह 30 एमएम गन, 7.62 एमएम पीकेटी और कॉकर्स मिसाइलों से लैस है।

10.40 क्यू आरएफवी (मीडियम)

क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत टाटा एंडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज ने तैयार किया है। यह गाड़ी 10 सशस्त्र सैन्य दलों को ले जाने सक्षम है। इस वाहन को लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदएश में तैनात सैनिकों के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है।

10.40 क्यू आरएफवी (हेवी)

यह वाहन माइन और बुलेट प्रूफ भी है। इसकी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रतिघंटा है। यह 25 ड्रिग्री तक चढ़ाई करने में सक्षम है।

10.41 के-9 वज्र टैंक

15 एमएम /52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड की फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर है। यह रेगिस्तानी इलाके में 60 किमी प्रतिघंटा से आगे बढ़ सकता है।

10.41 ब्रहोम्स प्रक्षेपात्र प्रणाली

यह देश में बना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिसकी रेंज 400 किमी है। यह सटीक और दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक लक्ष्य साधने में सक्षम है।

10.42 लघु अवधि बिजिंग प्रणाली (शार्ट स्पैन ब्रिज)

10 मीटर शार्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम एक यांत्रिक रुप से लॉन्च हमलावर ब्रिज है। जो कुछ मिनटों में नहर या नाले पर पुल तैयार कर दिया जाता है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है।

10.42 मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर

इस कॉलम में दो वाहन हैं। एक माइक्रोवैव नोड और उसके साथ मोबाइल नेटवर्क सेंटर। इससे सेना को युद्ध क्षेत्र में संचार के मामले में काफी मदद मिलती है। इसे भी देश में ही तैयार किया गया है।

10.43 आकाश आर्मी रडार

इसको डीआरडीओ ने देश में ही तैयार किया है। यह दुश्मन के हवाई प्लेटफार्म के खिलाफ कम दूरी की सतह से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को फायर करने में सक्षम है।

10.43 आकाश आर्मी लांचर

इस प्रणाली में 150 किलोमीटर तक एयरस्पेश की निगरानी करने और 25 किलोमीटर तक शत्रु के हवाई प्लेटफार्मों के प्रभावी ढ़ंग से उलझाए रखने में सक्षम है 12019 में बालाकोट हमले के बाद सीमा पर इसे तैनात किया गया है।

10.43 ध्रुव हेलीकाप्टर (फ्लाई पास्ट)

दो रुद्र और एक ध्रुव हैलीकॉप्टर उड़ान भर रहे है। आर्मी एवियशन का यह हेलीकॉप्टर काफी खतरनाक है। एक से हमला हो सकता है तो दूसरे से सैनिक और साजोसामन की आर्पूति हगो सकती है।

10.44 मैकेनाइज्ड इंफ्रैट्री रेजिमेंट

इसे आज की सेना में कल की रेजिमेंट के रुप में जाना जाता है। सेना में सबसे कम उम्र की रेजिमेंट है। आज यह ऐसी ताकत बन चुकी है जो भविष्य में किसी भी युद्ध क्षेत्र का तख्तापलट करने के लिए तैयार है। इसका युद्घोष है- बोल भारत माता की जय।

10.45 पंजाब रेजिमेंट सेंटर

यह भारतीय सेना की एकमात्र इन्फैंट्री रेजिमेंट है जिसके पास नौसेना का प्रतीक चिन्ह द गैली है। इसे सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट इन्फैंट्री में एक है। इसका युद्घोष है जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल।

10.46 मराठा लाइट इन्फैंट्री

यह सेना की सबसे पुरानी और सम्मानित रेजीमेंट में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षो से ज्यादा पुराना है। इसकी पहली बटालियन 1768 में स्थापित की गई। ये छत्रपति शिवाजी महराज से प्रेरणा लेते हैं। इनका युद्घोष है- बोल छत्रपति शिवाजी महराज की जय।

10.47 डोगरा रेजिमेंट सेंटर

इस रेजीमेंट का उद्भव ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 17वीं डोगरा रेजिमेंट से हुआ। डोगरा रेजिमेंट की यूनिटों ने आजादी के बाद के सारे जंग लड़े है। इस रेजीमेंट के जवान हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब से आते हैं।

10.48 बिहार रेजीमेंट सेन्टर

बिहार रेजीमेंट की पहली बटालियन की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इस रेजीमेंट में 50 फिसदी बिहार के और 50 फिसदी आदिवासी है। इसका युद्धघोष है बोल बजरंग बली की जय

10.49 गोरखा ब्रिगेड

गोरखा ब्रिगेड भारत और नेपाल के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधो का प्रमाण है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशा ने एक दफा कहा था कि अगर कोई कहता है कि वह मरने से नही डरता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है।

10.50 पूर्व सैनिकों की झांकी

अमृत काल की दिशा पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता को दिखाती है। भारत का भाग्य बदलने की दिशा में उनकी पहलों को मान्यता देने का प्रतीक है। यह पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है।

10.52 भारतीय नौसेना

तीनों सेनाओ में सबसे छोटी है। बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेंकड क्लास एम एंथनी राज की अगुवाई में जय भारती की धुन बजाते हुए। 80 बैंड वादकों के साथ।

नौसेना की दस्ते की अगुवाई लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृथ कर रही है। इस दस्ते में 03 महिला अफसर और 05 अग्निवीर शामिल हुए हैं। झांकी में नारी शक्ति के बहुआयामों को दिखाया गया है।

10.52 वायुसेना

10.53 बाज फॉरमेशन में तीन मिग-29

वायुसेना का दस्ता स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी की अगुवाई में। इसमें 144 जवान 03 अफसर शामिल है। झांकी में दिख रहा है सीमाओं से आगे भारतीय वायुसेना की शक्ति। एक ग्लोब के जरिये वायुसेना की पहुंच को दिखाया गया है। मानवीय सहायता से लेकर मित्र देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास तक।

10.54 डीआरडीओ

रक्षा अुनसंधान एवं विकास संगठन एक प्रमुख अुनसंधान एवं विकास संगठन है। जो सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार व साजोसमान बनाता है। डीआरडीओ की झांकी में प्रभावी निगरानी तथा संचार से राष्ट्र की सुरक्षा व खतरों का शमन है। यह आकाश, सतह और पानी के अंदर दुशमन के खतरों की निगरानी के विभन्न तकनीकियों को प्रदर्शित करता है।

10.55 70 टन ट्रेलर पर व्हील्ड आर्मड प्लेटफार्म

इसे डीआरडीओ ने देश में डिजाइन और विकसित किया है। यह वाहन नदी और नहरों को आसानी से पार कर सकता है। सड़क पर इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है। 70 टन का ट्रेलर बेहतर गतिशीलता के साथ अत्याधुनिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन पर भारी पेलोड को लोड करने और उतारने के लिए स्टीयरेबल एक्सल और हाइड्रोलिक रैंप से लैस है।

10.56 असम रेजीमेंट

इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। इस दस्ते में देशभर से भर्ती किये गये सैनिक शामिल है जो विविधता में एकता की मिसाल है। 187 सालों का इतिहास 994 बहादुरों के बलिदान स्तंभों पर बना है।

खादर में 39 हेक्टेयर गन्ने की फसल होगी नीलाम

हस्तिनापुर (मेरठ)। खादर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से खेती करने वाले भूमाफिया पर जल्द ही कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र में 39 हेक्टेयर सरकारी भूमि चिह्नित की है। उस भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को नीलाम किया जाएगा।

मवाना तहसील के तहत गंगा पार बिजनौर की ओर हजारों हेक्टेयर सरकारी भूमि है। कुछ भूमाफिया सालों से हजारों हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं। इससे राजस्व विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है। वह गंगा को भी प्रदूषित कर रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों पर डीएम ने 16 जनवरी को खादर क्षेत्र में गंगा की गतिविधियों की जानकारी के लिए सात सदस्यीय टीम गठित की थी। टीम से दस दिनों में रिपोर्ट मांगी गई थी। टीम का अध्यक्ष एसडीएम मवाना अखिलेश यादव को बनाया गया था।

गंगा पार होने का उठाते हैं फायदा

मवाना तहसील की राजस्व भूमि गंगा के पार है। यहां बिजनौर क्षेत्र के भूमाफिया अवैध रूप से कब्जा कर खेती करते हैं। तहसील प्रशासन ने कई बार चेतावनी दी। इसके बाद भी भूमि खाली नहीं की गई। अब प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। वहीं 39 हेक्टेयर भूमि चिह्नित होने की खबर से भूमाफिया में खलबली मच गई है।

मनोहरपुर के जंगल में 325 हेक्टेयर सरकारी भूमि

मनोहरपुर निवासी मुनेश कुमार ने बताया कि उनका गांव गंगा में समा चुका है। उनकी लगानी भूमि पर गंगा की धारा है। सरकारी भूमि पर बिजनौर के भू माफिया का कब्जा है। 325 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से खेती हो रही है। शिकायत के बाद भी आज तक भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका है।

खादर क्षेत्र के शेरपुर और बुआ बेला में 39 हेक्टेयर सरकारी भूमि को चिह्नित किया गया है। इस जमीन पर वर्तमान में गन्ने की फसल है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। अनुमति मिलते ही इस फसल को नीलाम किया जाएगा। अन्य कई गांवों में मौजूद सरकारी भूमि को भी चिह्नित किया जा रहा है। - अखिलेश यादव, एसडीएम

रैपिड रेल : साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक 5.50 किमी सुरंग निर्माण पूरा

एनटीवी न्यूज

गाजियाबाद। रैपिड रेल के 82 किमी लंबे कॉरिडोर में 12 किमी के भूमिगत भाग के निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है। आनंद विहार से न्यू अशोकनगर दिल्ली तक भूमिगत हिस्से की लंबाई तीन किमी तो आनंद विहार से साहिबाबाद तक सुरंग की लंबाई दो किमी है। ऐसे में साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक भूमिगत हिस्से में समानांतर कुल 10 किमी में से 5.50 किमी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) की ओर से दिल्ली में भूमिगत भाग में अब तक पहले से तैयार 25,600 टनल सीमेंट के हिस्से (प्री-कास्ट सेगमेंट) का इस्तेमाल किया गया जा चुका है। दिल्ली से साहिबाबाद तक 10 किमी के भाग में सुरंग निर्माण के लिए चार टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) सुदर्शन लगातार कार्य कर रही हैं। भूमिगत भाग में रैपिड रेल के आने जाने के लिए समानांतर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में आनंद विहार से न्यू अशोकनगर के बीच करीब चार किमी सुरंग की खोदाई हो चुकी है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स का कहना है कि कॉरिडोर के भूमिगत भाग पर निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक चारों टनल बोरिंग मशीन कार्य कर रही हैं।

मेरठ में भी 11 में से पांच किमी की सुरंग बनी रैपिड रेल के मेरठ में कुल 11 किमी लंबी समानांतर सुरंग का निर्माण होना है, इसमें से करीब पांच किमी की टनल का सफलता पूर्वक काम हो चुका है। मेरठ में भैंसाली से मेरठ सेंट्रल के बीच दो किमी लंबे सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं मेरठ के बेगमपुर में 750 मीटर लंबी पहली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यहां भी एनसीआरटीसी की ओर से अब तक पहले से तैयार 21,000 टनल सीमेंट के हिस्से (प्री-कास्ट सेगमेंट रिंग्स) का इस्तेमाल किया गया जा चुका है। सुरंग में इस्तेमाल होने वाली टनल रिंग्स का निर्माण एनसीआरटीसी के वसुंधरा और मेरठ स्थित यार्ड में किया जा रहा है।

दिसंबर 2023 तक सुरंग का निर्माण का लक्ष्य

साहिबाबाद से दुहाई तक प्राथमिकता खंड पर रैपिड रेल का संचालन मार्च 2023 में प्रस्तावित है। दूसरी ओर दुहाई से मेरठ दक्षिण तक के दूसरे खंड पर रेल का संचालन अक्तूबर 2023 में शुरू होगा। ऐसे में एनसीआरटीसी की योजना दिसंबर 2023 तक सुरंग का निर्माण कार्य पूरा करने की है। साहिबाबाद से दिल्ली सराय काले खां तक के खंड पर रैपिड रेल का संचालन मई 2024 में शुरू होना है। वर्तमान में प्राथमिकता खंड पर हाईस्पीड टेस्टिंग ट्रायल लगातार जारी हैं। रेल को न्यूनतम 100 किमी तो अधिकतम 160 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ाया जा रहा है।

इनसाइड

एमबीए पास प्रधान ने ग्राम पंचायत को सीसीटीवी कैमरों और वाई-फाई से बनाया हाईटेक

शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर ग्रामीणों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई - सरकारी भवनों पर सुरक्षा के लिए लिहाज से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे कब्जामुक्त कराई सरकारी जमीन गाजियाबाद एमबीए पास प्रधान ने ग्राम पंचायत को सीसीटीवी कैमरों और वाई-फाई से बनाया हाईटेक

गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि ग्राम पंचायतें भी शहर की तरह माडर्न हों। वहां पर रहने वालों को शहर की सोसायटियों की तरह ही शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया हों, जिससे कि दूर न जाना पड़े। ऐसी ही एक ग्राम पंचायत है गाजियाबाद के लोनी ब्लाक की शकलपुरा, जो भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राजेश पायलट की ससुराल भी है। इस ग्राम पंचायत को माडर्न बनाने का कार्य इन दिनों इस गांव के प्रधान रवि कुमार कर रहे हैं। जो एमबीए की पढ़ाई पूरी कर तीन साल पहले एक कंपनी में चार लाख के पैकेज पर नौकरी करते थे। लेकिन कोरोना काल में ग्राम पंचायत के लोगों की मदद के लिए किए गए प्रयास ने रवि को उनके साथ इस तरह जोड़ा कि उन्होंने उन्होंने चार लाख रुपये का पैकेज छोड़कर पहली बार ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा, जिसमें कामयाबी मिली तो जो कार्य वर्षों से नहीं हो सके, उसको प्राथमिकता दी। यही वजह है कि ग्राम पंचायत में आज स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन बनकर तैयार है तो दूसरी तरफ तालाब के सुंदरीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है, सालों से कब्जा की गई बरात घर की जमीन अब कब्जामुक्त है।

RTE के तहत सैकड़ों बच्चों को दिलाया स्कूलों में प्रवेश, बिना अभिभावकों के बच्चों के लिए भी बनाई शिक्षा की डगर

घर की हालत तो ऐसी नहीं थी कि इतने बड़े स्कूल में पढ़ सकें यहां बच्चे महंगी कार और स्कूल बस से आते हैं और हमें आज भी साइकिल से पापा स्कूल छोड़ते हैं। शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चों की कहानी इससे बहुत कुछ मिलती।

नोएडा। घर की हालत तो ऐसी नहीं थी कि इतने बड़े स्कूल में पढ़ सकें, यहां बच्चे महंगी कार और स्कूल बस से आते हैं और हमें आज भी साइकिल से पापा स्कूल छोड़ते हैं। शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चों की कहानी इससे बहुत कुछ मिलती है। इन बच्चों के अभिभावक आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वे किसी भी निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन सरकार की शिक्षा का अधिकार (आरटीई) योजना और पहल संस्था ने न सिर्फ बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया, बल्कि उन्हें पढ़ाई के लिए एक बेहतर वातावरण भी मिला है।

RTE के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को दिलाया प्रवेश

संस्था द्वारा अब तक करीब एक हजार बच्चों को निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश दिलाया जा चुका है। हालांकि यह कार्य आसान नहीं रहा। कई स्कूलों ने आरटीई में प्रवेश देने के नाम पर स्कूल में ही कदम नहीं रखने दिया। कई स्कूलों के बाहर अभिभावकों को लेकर कई-कई दिन तक धरना देने के साथ प्रदर्शन भी करना पड़ा। स्कूल से लेकर बीएसए कार्यालय के चक्कर भी लगाने पड़े। कोरोना काल में जब स्कूल खुले तो बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन अधिकांश स्कूल आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को प्रवेश देने को तैयार नहीं थे। कई जगह तो उगाही किए जाने का आरोप लगाने की धमकी भी दी गई, लेकिन जब अभिभावक साथ होते थे, तो स्कूल प्रबंधन को मामला समझ में आता था, हालांकि इसके बाद भी खूब जद्दोजहद करनी पड़ी। जो आज भी जारी है।

कई स्कूलों के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया

दो वर्ष पहले शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक लोटस वैली, स्टेप बाइ स्टेप, डीपीएस, विश्व भारती, मानव रचना, मिलेनियन स्कूल, खेतान पब्लिक स्कूल, एस्टर पब्लिक स्कूल, राघव ग्लोबल, इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल, जेनेसिस ग्लोबल स्कूल, कोठारी इंटरनेशनल, डीएवी, डीपीएस वर्ल्ड स्कूल, फ्लोरेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, गौर इंटरनेशनल स्कूल, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, सफायर इंटरनेशनल स्कूल, एलपीएस ग्लोबल स्कूल सहित कई और स्कूलों में एक हजार बच्चों को प्रवेश दिलाने में सफलता मिली। इसके लिए जेनेसिस ग्लोबल स्कूल, इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल, डीपीएस, विश्व भारती, राघव ग्लोबल, मानव रचना, रामाज्ञा स्कूल, फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल और बाल भारती सहित कई स्कूलों के बाहर अभिभावकों को साथ लेकर लगातार प्रदर्शन करने पड़े थे। मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए मदद भी की थी। जिसके कारण यह योजना सार्थक होती नजर आ रही है बच्चों को बेहतर शिक्षा का मौका मिल रहा है।

संस्था के प्रयास से ही गौतमबुद्ध नगर पूरे प्रदेश में आरटीई में प्रवेश देने के नाम पर दूसरे पायदान पर आ गया है। पहल संस्था के संस्थापक अविनाश सिंह ने राजेश अंबावता और अनिल सिंह के साथ मिलकर संस्था का गठन किया। इसके बाद अविनाश सिंह ने इस बात की पड़ताल करनी शुरू की कि जो अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश आरटीई के स्कूल में कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनमें से कितने बच्चों को प्रवेश मिल सका। जिन बच्चों को प्रवेश नहीं मिला, उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने अभिभावकों को साथ लेकर स्कूल के बाहर धरना-प्रदर्शन तक किया। इसके बाद समाज के गरीब वर्ग के लोगों को आरटीई के बारे में जागरूक करने का कार्य शुरू किया। इसमें लोगों को बताया कि वे भले ही निजी स्कूलों की महंगी फीस का बोझ वहन करने में सक्षम नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे परिवार के बच्चों को बिना फीस के प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। जिससे वे बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

पत्नी छोड़कर गई तो मानसिक तनाव के चलते जेल जाना चाहता था शख्स, रेलवे स्टेशन पर बम की दी फर्जी सूचना; गिरफ्तार

गणतंत्र दिवस से पहले गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर बम होने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन-फानन में डाग व बम स्क्वाड के साथ पहुंचकर तलाशी ली पर बम नहीं मिला।

गाजियाबाद। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले बुधवार की सुबह पुराना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर बम होने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन-फानन में डाग व बम स्क्वाड के साथ पहुंचकर तलाशी ली, पर बम नहीं मिला। फर्जी सूचना के आधार पर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह घरेलू कलह के चलते तनाव में है और जेल जाना चाहता है। इसके चलते उसने पुलिस को बम की फर्जी सूचना दी थी।

मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा ?

एसीपी कोतवाली अंशु जैन का कहना है कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर एक युवक ने सूचना दी थी कि उसने पुराना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर बम फिट कर दिया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया तो बम नहीं मिला, सूचना फर्जी निकली। पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस कर आरोपित को दबोच लिया। एसीपी का कहना है कि पकड़ा गया आरोपित इटावा के कायस्थ टोला के करनपुर का हर्षित दीक्षित है।

मानसिक तनाव के चलते उठाया यह कदम

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसने परिवार की मर्जी के विपरीत पांच साल पूर्व दूसरे धर्म की युवती से शादी कर ली थी। इसके बाद परिवार ने उसे अलग कर दिया था। इसके बाद वह पत्नी के साथ दिल्ली आकर रहने लगा और एक मैरिज होम में मैनेजर की नौकरी करने लगा। शादी के कुछ समय बाद पत्नी छोड़कर चली गई और वह तनाव में रहने लगा। परिवार ने भी इटावा के मकान में प्रवेश नहीं दिया।

तनाव के चलते उसने दो दिन पहले नौकरी भी छोड़ दी थी। मानसिक तनाव के कारण वह जेल जाना चाहता था। इसके चलते वह बुधवार को ट्रेन से दिल्ली से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आया और पुलिस को बम की फर्जी सूचना दी। जांच में आया है कि आरोपित पर इटावा में अपहरण का एक मुकदमा दर्ज है।

इनसाइड

होने वाली है इन धांसू गाड़ियों की एंट्री, लिस्ट में महिंद्रा और टाटा का भी नाम शामिल

नए साल की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बाकी है। इसके साथ ही भारतीय बाजार में कई वाहन निर्माता कंपनियां भी अपनी नई गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी में है।टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस अगले साल अपनी एंट्री मारने वाली है।

नईदिल्ली। अगर आप अपने लिए एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो भारतीय बाजार में अगले साल 2023 में कई नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली है। आज हम आपके लिए इन गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आप एक नई शानदार कार खरीद सकते हैं। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस अगले साल अपनी एंट्री मारने वाली है। आपको बता दे मॉडल को 172bhp, 2.0L स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल और 186bhp, 2.0L मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। ये 7-सीटों या 8-सीटों के लेआउट के साथ आ सकती है। हाइब्रिड MPV को ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम) के Toyota सेफ्टी सेंस सूट के साथ पैक किया गया है. इसमें फीचर्स के तौर पर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हवादार फ्रंट सीटें, 9-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम, दूसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए पावर्ड लेग रेस्ट, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई है।

MAHINDRA XUV400

महिंद्रा भारतीय बाजार में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली कंपनी में से एक है। ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक, ईवी तीन वेरिएंट्स- बेस, ईपी और ईएल में आएगी। इसके सभी वेरिएंट 39.4kWh बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर (150bhp / 310Nm) द्वारा संचालित होते हैं। यह 8.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। महिंद्रा की नई एसयूवी फुल चार्ज पर 456 किमी की सर्टिफाइड रेंज देती है। इसमें आपको तीन ड्राइविंग मोड - फन, फास्ट और फीयरलेस के साथ-साथ सेगमेंट-फर्स्ट सिंगल पेडल ड्राइव मोड - लाइवली मोड भी मिलता है।

Tata Tiago EV

टाटा की ये एक इलेक्ट्रिक हैचबैक है। जनवरी में ये कार लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। कंपनी ने इसकी कीमतों की घोषणा पहले ही कर दी है। इसकी कीमत 8.49 लाख रुपये से शुरू होकर 11.79 लाख रुपये तक जाती है। इसके साथ ही देशभर में इसकी बुकिंग पहले से चालू भी हो चूकी है। Tata Tiago EV में 19.2kWh या 24kWh बैटरी पैक मिलता है। सेटअप छोटे बैटरी पैक के साथ 61bhp की अधिकतम शक्ति और 110Nm का टार्क और बडे बैटरी पैक के साथ 114 Nm के साथ 74bhp की टॉर्क जनरेट करती है.

BYD Atto 3

भारतीय बाजार में इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 33.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ये अगले साल लॉन्च होने वाली सबसे प्रमुख कारों में से एक है। आपको बता दे इस कार की अब तक 1500 से अधिक की बुकिंग हो चुकी है। कंपनी ने ये दावा किया है कि इसकी डिलीवरी अगले साल जनवरी 2023 से शुरु हो जाएगी। यह 60kWh BYD ब्लेड बैटरी और एक स्थायी चुंबक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है। ये 201bhp की पीक पावर और 310Nm का टार्क जनरेट करती है। एट्टो 3 एक बार चार्ज करने पर 521 किमी की एआरएआई-प्रमाणित रेंज प्रदान करता है। यह 7.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी बैटरी को 50 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज हो सकती है।

ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है भारत, ईवी के सप्लाई चेन में भी होगा सबसे आगे

ऑटोमोबाइल के कई बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले में समय में भारत ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। इसके साथ ही टाटा मोटर्स के एमडी ने कहा है कि भारत ईवी के वैश्विक हब व सप्लाई चेन का एक प्रमुख केंद्र बनने की राह पर है।

ऑटोमोबाइल के कई बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले में समय में भारत ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। इसके साथ ही टाटा मोटर्स के एमडी ने कहा है कि भारत ईवी के वैश्विक हब व सप्लाई चेन का एक प्रमुख केंद्र बनने की राह पर है।

नई दिल्ली। देश की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी टाटा मोटर्स का कहना है कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक हब व सप्लाई चेन का एक प्रमुख केंद्र बनने की राह पर अग्रसर है और टाटा मोटर्स भी इसके हिसाब से ही अपनी रणनीति तैयार कर रही है। दूसरी कार कंपनियों की तरह टाटा मोटर्स सिर्फ पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार तक ही सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि लंबी दूरी तय करने वाले हेवी ट्रकों से लेकर गली-मोहल्लों में चलने वाले छोटे कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन भी बनाने की योजना पर काम कर रही है। टाटा मोटर्स ने बताया है कि वर्ष 2030 तक उसके कुल वाहन उत्पादन का 50 फीसद इलेक्ट्रिकवाहनों का होगा। कंपनी लंबी दूरी के ट्रकों को बिजली चालित बनाने के लिए भारी-भरकम राशि इसके शोध व विकास पर खर्च कर रही है।

भारत होगा ईवी का वैश्विक आपूर्ति केंद्र

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स व टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एमडी शैलेश चंद्रा ने बताया कि उनकी कंपनी यह सोच कर अपनी रणनीति बना रही है कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का एक वैश्विक आपूर्ति केंद्र और बड़ा निर्यातक के तौर पर स्थापित होगा।

चंद्रा का कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत और विश्व के दूसरे ऑटोमोबाइल बाजार एक साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के रास्ते पर जा रहे हैं। अभी तक पेट्रोल व डीजल से चलने वाले आटोमोबाइल में उन्नत तकनीक लंबे अरसे बाद भारत आती थी। दुनिया के किसी भी दूसरे देश के पास ईवी को बढ़ावा देने वाली भारत जैसा माहौल नहीं है।

ईवी निर्माण में भी भारत है कुशल

मसलन, यहां बहुत ही बड़ा बाजार है, कार खरीदने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्माण के लिए जैसा कार्यकुशल श्रम चाहिए वैसा भारत के पास है, इलेक्ट्रिक वाहनों में सॉफ्टवेयर का बहुत योगदान होता है और भारत जैसा सॉफ्टवेयर प्रतिभा और कहीं नहीं मिलेगा। सुजुकी मोटर कार्पोरेशन (एसएमसी) के निदेशक तोशीहीरो सुजुकी भी मानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आटो बाजार बनने की क्षमता रखता है। लेकिन इसमें वक्त लगेगा।

सबसे बड़ा आटोमोबाइल बाजार बन सकता भारत

पिछले वर्ष भारत में कुल 42.5 वाहनों की बिक्री हुई है जबकि अभी तक तीसरे नंबर पर रहने वाले देश जापान में 42 लाख वाहनों की बिक्री हुई है। चीन पहले स्थान पर (2.6 करोड़ बिक्री) व अमेरिका दूसरे स्थान (1.54 करोड़) पर है। हुंडई मोटर इंडिया के एमडी अनसू किम ने भी बताया कि भारत सबसे बड़ा आटोमोबाइल बाजार बन सकता है। मारुति सुजुकी और हुंडई की भावी योजनाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों का बहुत बड़ी भूमिका होगी। हुंडई 4000 करोड़ रुपये के नये निवेश से आठ इवी वर्ष 2027-28 तक लांच करना चाहती है। मारुति सुजुकी इवी को लेकर अभी बहुत खुल कर कुछ नहीं कह रही। उक्त तीनों कंपनियां यह मानती हैं कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए हैं उसका काफी फायदा पूरे उद्योग को होगा।

स्पोर्ट्स कार पोर्श 718 जीटी4 ट्रैक वाला वेरिएंट है और इसका वजन स्टैंडर्ड वर्जन से 35 किलोग्राम हल्का है।इसकी तुलना स्टैंडर्ड मॉडल से करें तो इसमें अपग्रेड के मामले में 718 GT4 RS में फोर्ज्ड एल्युमिनियम व्हील्स मिलता है।

बुलेट ट्रेन का मजा देगी पोर्से 718 कैमैन GT4 RS, 'फेस्टिवल ऑफ ड्रीम' में हुई शोकेस

नई दिल्ली। पोर्श इंडिया ने मुंबई में आयोजित अपने 'फेस्टिवल ऑफ ड्रीम्स' कार्यक्रम में पोर्श इंडिया भारत में पहली 718 GT4 RS लेकर आ गई है। इस कार में 4-लीटर फ्लैट-सिक्स एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो 315 किमी प्रति घंटे की स्पीड के साथ 493 hp और 450 Nm का टार्क जनरेट करता है। इसका वजन मानक 718 जीटी4 वेरिएंट की तुलना में 35 किलोग्राम हल्का है और इसमें बेहतर ट्रैक प्रदर्शन के लिए मैन्युअल रूप से समायोज्य फ्रंट सप्लिटर और रियर स्पॉइलर है। यह जीटी4 आरएस पहली 718 है जिसमें पहियों पर पोर्श का सिंगल-लॉक लगा है और ब्रेकिंग के लिए आगे 408 मिमी डिस्क और पीछे 380 मिमी डिस्क मिलती है। जबकि इस स्पोर्ट्स कार की कीमत 2.53 करोड़ रुपये के एक्स-शोरूम से शुरू होकर 3.2 करोड़ रुपये के करीब तक है।

स्टैंडर्ड मॉडल

इसकी तुलना स्टैंडर्ड मॉडल से करें तो इसमें अपग्रेड के मामले में, 718 GT4 RS में फोर्ज्ड एल्युमिनियम व्हील्स, फ्रंट में 408 mm डिस्क और रियर में 380 mm डिस्क हैं। निलंबन और चेसिस को भी आरएस के लिए फिर से तैयार किया गया है और बेहतर ट्रैक प्रदर्शन के लिए 30 मिमी कम किया जा सकता है। इसमें सबसे अहम बात ये है कि 26 जनवरी को स्पोर्ट्स कार आम जनता के लिए भी शोकेस की जाएगी वो भी इसे निः शुल्क देख सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं तो www.festivalofdreams.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

जीटी 4 आरएस

स्टैंडर्ड मॉडल केमैन की तुलना में, जीटी 4 आरएस को नए बम्पर के साथ बड़े एयर इंटेक्स और फ्रंट स्प्लिट के साथ बहुत अधिक आक्रामक लुक मिलता है। हुड में एयर वेंट्स मिलते हैं और फिर स्पोर्ट्स कार के पीछे बड़ा स्पॉइलर होता है जिसमें 3 मैनुअल एडजस्टमेंट होते हैं। जीटी 4 आरएस के फ्रंट फेंडर भी चौड़े और अधिक आक्रामक रूप से डिजाइन किए गए हैं। कार में रियर फेंडर पर इनटेक वेंट भी बड़ा है। वाहन का वजन कुल 1,415 किलोग्राम है।

मारुति सुजुकी बलेनो को टक्कर देने आ गई Tata Altroz Racer

टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में अल्ट्रोज़ रेसर के साथ एक स्पोर्टी हैचबैक को शोकेस किया है। इंडियन मार्केट में अगर ये कार आई तो इसकी टक्कर हुंडई आई20 एन लाइन से होगी। इसके डिजाइन में कोई भी खास बदलाव नहीं किया गया है।

नईदिल्ली। भारतीय बाजार में इस बार ऑटो एक्सपो 2023 में टाटा ने अपना जादू बिखेरा हुआ है। टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में अल्ट्रोज़ रेसर के साथ एक स्पोर्टी हैचबैक को शोकेस किया है। टाटा अल्ट्रोज़ रेसर स्टाइलिंग कई बदलाव और एक नई इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कई कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड के साथ आता है। इंडियन मार्केट में अगर ये कार आई तो इसकी टक्कर हुंडई आई20 एन लाइन से होगी।

Tata Altroz Racer

Tata Altroz Racer को लाल और काले रंग के डुअल-टोन पेंट स्कीम में फिनिश किया गया है। बोनट, ओआरवीएम और रुफ को बीच में सफेद धारियों के साथ काला कर दिया गया है जो दिखने में काफी दमदार लगता है। इसके लुक को और बढ़ाने के लिए अलॉय व्हील्स को ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी मिलता है। हालाकिं इसके डिजाइन में कोई भी खास बदलाव नहीं किया गया है। टाटा अल्ट्रोज़ रेसर को डुअल-टोन पेंट स्कीम भी मिलती है।

ऑल-ब्लैक कलर स्कीम

केबिन के अंदर इसे ऑल-ब्लैक कलर स्कीम और नए और बड़े 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ बड़ा अपडेट मिलता है। वहीं इस दमदार कार में एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी है, जो मौजूदा वर्जन के सेमी-डिजिटल यूनिट की जगह को लेता है। अल्ट्रोज़ रेसर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वॉयस-एक्टिवेटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग और एक एयर प्यूरीफायर के साथ आती है।

इंजन

टाटा अल्ट्रोज़ रेसर नेक्सन में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इसका मोटर 120 बीएचपी और 170 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है। जिसे 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। आपको बता दें, टाटा ने अभी तक इसे लॉन्च करने की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा अनुमान माना जाता है कि इस साल के अंत तक कंपनी इसे ला सकती है। इसके दमदार फीचर्स और लुक के कारण हैचबैक का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा से होगा।

संकट के दौर में आस्था के पहाड़

प्रताप सिंह पटियाल

उत्तराखंड़ में स्थापित 'ज्योतिर्मठ' को वर्तमान में जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। विख्यात तीर्थस्थल बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव भी जोशीमठ ही है। सैकड़ों वर्ष पूर्व 'गिरिराज चक्रचूड़ामणि' पदवीधारी 'कत्यूरी' राजवंश के सूर्यवंशी राजाओं की पहली राजधानी जोशीमठ ही थी।

जोशीमठ जैसी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा का नाम देने से पहले पहाड़ों पर इनसानी दखलअंदाजी से हो रही घटनाओं पर रायशुमारी होनी चाहिए। इनसानी सभ्यता के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए भूगर्भ वैज्ञानिकों की नसीहत व निर्देशों को संजीदगी से लेना होगा। जोशीमठ को हर कीमत पर बचाना होगा'

पृथ्वी पर कुदरत की सबसे खूबसूरत व संवेदनशील रचना पहाड़ हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय राज्यों में शुमार करते हैं। सनातन संस्कृति में अनादिकाल से पर्वत करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहे हैं। एकांत में सुकून के पल बिताने के लिए देश-विदेश से लाखों पर्यटक प्रति वर्ष पहाड़ों का रुख करते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र सैंकड़ों मंदिर पहाड़ों पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ समय से आस्था के पहाड़ पर्यटकों की भारी भीड़, बढ़ती आबादी का बोझ व बढ़ते शहरीकरण तथा ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आकर कई आपदाओं के दौर से गुजर रहे हैं। भूस्खलन, हिमस्खलन, ग्लेशियर पिघलने व बादल फटने से सैलाब जैसी सूरतेहाल में पहाड़ों का तवाजुन बिगडने से पर्वत दरक रहे हैं, मगर आपदाओं की कीमत पहाड़ों पर निवास करने वाले लोग चुका रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में प्राचीन पौराणिक शहर जोशीमठ भू-धंसाव के कारण भयंकर विपदा का सामना कर रहा है। स्मरण रहे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा तथा पवित्र चार वेदों को सुरक्षित रखने के लिए सनातन धर्म के महान ध्वजवाहक 'आदि शंकराचार्य' ने सदियों पूर्व भारत की चार दिशाओं में चार शंकराचार्यों के नेतृत्व में चार मठों की स्थापना करके इन मठों को चारों वेदों से जोडक़र भारत की सांस्कृतिक एकता को कायम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अद्वैत वेदांत के प्रर्वतक महान संत शंकराचार्य ने अपनी युवा अवस्था में ही सनातन संस्कृति की रक्षा का बीड़ा उठा लिया था।

उत्तराखंड़ में स्थापित 'ज्योतिर्मठ' को वर्तमान में जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। विख्यात तीर्थस्थल बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव भी जोशीमठ ही है। सैकड़ों वर्ष पूर्व 'गिरिराज चक्रचूड़ामणि' पदवीधारी 'कत्यूरी' राजवंश के सूर्यवंशी राजाओं की पहली राजधानी जोशीमठ ही थी। उन राजाओं ने अपनी रियासत को 'कूर्मांचल' अर्थात कूर्म की भूमि (भगवान विष्णु की भूमि) नाम दिया था। मान्यता है कि

हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद श्री विष्णु अवतार 'नरसिंह भगवान' अपने भयंकर क्रोध को शांत करने के लिए इसी पर्वत पर पहुंचे थे। हल्द्वानी के 'रानीबाग' क्षेत्र के युद्ध में कुमाऊं के राजपूतों की सेना के साथ उसी कत्यूरी राजवंश की वीरांगना 'जिया रानी' (1380-1420) ने तुर्क शासक तैमूर लंग की मुगल सेना को अपनी शमशीर से हलाक करके बेदखल किया था। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं में जिया रानी का जिक्र पूरी अकीदत से होता है। वीरभूमि व देवभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल व उत्तराखंड दोनों राज्यों में भौगौलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व सैन्य क्षेत्र में कई समानताएं हैं। उत्तराखंड में भारत के प्रथम 'परमवीर चक्र' मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम बड़े अदब के लिया जाता है। हिमाचल के उस शूरवीर का संबंध 'कुमाऊं रेजिमेंट' से था। कश्मीर को पाक सेना से बचाने के लिए बडग़ाम की जंग में 3 नवंबर 1947 के दिन मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ 'चौथी कुमाऊं' बटालियन के सूबेदार प्रेम सिंह मेहता, नायक 'नर सिंह' व 'दीवान सिंह' दोनों 'महावीर चक्र' सहित 20 जवानों ने शहादत जैसे अजीम रुतबे को मिलकर गले लगा लिया था। दोनों राज्यों के सैनिकों का एक साथ फिदा-ए-वतन का रिश्ता बहुत कुछ बयान करता है। हिमाचल के कर्नल कमान सिंह पठानिया 'महावीर चक्र' की कमान में '3 गढ़वाल' के सैनिकों ने पाकसेना को शिकस्त देकर 18 मई 1948 को कश्मीर के टिथवाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।

भावार्थ यह है कि उत्तराखंड में केवल बद्रिकाश्रम का भू-भाग ही नहीं दरक रहा बल्कि भारत की प्राचीनतम सनातन संस्कृति, ऋषियों की तपोस्थली, आस्था व वंदन की भूमि एवं शौर्य-पराक्रम का धरातल तथा कत्यूरी साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास संजोए जोशीमठ जमींदोज होने की कगार पर पहुंच चुका है। 'गेटवे ऑफ हिमालय' कहा जाने वाला जोशीमठ चीन के करीब होने से वहां हजारों सैन्यबलों की तैनाती भी की गई है। जोशीमठ में खौफनाक आपदा के बाद 'राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति' (एनसीएमसी) ने अपनी खामोशी तोडक़र हरकत में आकर लोगों से उस क्षेत्र को खाली करने का फरमान जारी कर दिया। सैकड़ों भवनों में दरारें आने के कारण जोशीमठ का इलाका स्थानीय लोगों की रिहाइश के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के नाम पर चलने वाली ज्यादातर परियोजनाओं के लिए हरियाली से सराबोर जंगलों को मशीनों के प्रहारों से उजाड़ कर पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है।

अनियंत्रित विकास की इस आंधी का खामियाजा स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ता है। वर्तमान में प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, पर्यावरण से हो रहा खिलवाड़, पहाड़ों पर अतिक्रमण, आस्था की नदियों का मैला हो रहा दामन, खड्डों में अवैध खनन तथा परंपरागत पेयजल स्रोतों का मिटता वजूद हमारे शासन, प्रशासन व संबंधित विभागों की बेरुखी का नतीजा है, जबकि इन संवेदनशील मुद्दों पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सामरिक दृष्टि से अहम पहाड़ी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का खाका तैयार करने वाले मंत्रालयों के अहलकारों को बेघर हो रहे लोगों के अश्कों का दर्द भी समझना होगा। तबाही को अंजाम देने वाले विकास कार्यों से उपजी विनाश लीला जो लोगों के आशियाने छीन कर विस्थापन का दंश झेलने पर मजबूर कर दे, उसका कोई औचित्य नहीं है। पहाड़ की भोली-भाली विरासत के लोगों की पुश्तैनी विरासतों तथा गौरवमयी व खुशहाल अतीत की कीमत सरकारी मुआवजे के चंद नोटों से अदा नहीं की जा सकती। जोशीमठ जैसी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा का नाम देने से पहले पहाड़ों पर इंसानी दखलअंदाजी से हो रही घटनाओं पर रायशुमारी होनी चाहिए। इनसानी सभ्यता के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए भूगर्भ वैज्ञानिकों की नसीहत व निर्देशों को संजीदगी से लेना होगा। बहरहाल 'अययात्मा ब्रह्म' का आध्यात्मिक संदेश देने वाला प्राचीन वैदिक शिक्षा का केंद्र 'ज्योतिर्मठ' अथर्ववेद से संबंधित है। अतः जोशीमठ को सुरक्षित रखने के हर स्तर पर प्रयास होने चाहिए। कुदरत की प्रतिशोध भरी प्रतिक्रिया से उपजी आपदा पर वैज्ञानिक तरीके से मंथन होना चाहिए ताकि पहाड़ों व धार्मिक स्थलों का स्वरूप सुरक्षित रहे।

संपादक की कलम से

पूर्ण राज्यत्व की पूर्णता

आधी सदी का इतिहास और सबक हिमाचल के भविष्य की कल्पना में सुक्खू सरकार के अगले पांच साल के सफर को देख रहे हैं, लिहाजा अपने पहले शासकीय संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस का शृंगार किया है। सरकार ने 'एरिया ऑफ एक्शन' चिन्हित करते हुए पहले ही ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जबकि व्यवस्था परिवर्तन के तहत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का निलंबन, सीमेंट उद्योग पर नकेल, मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल तथा 101 करोड़ की सुख आश्रय जैसी दूरगामी योजनाओं का श्रीगणेश किया है। हिमाचल सरकार ने पूर्व में घोषित नौ सौ के करीब दफ्तर या सरकारी संस्थान बंद करके कडक़ संदेश दिया है, तो नई उपलब्धियां जोडऩे के लिए अपने मंत्रियों व मुख्य संसदीय सचिवों की टीम बनाई है। किसी भी सरकार से विकास की परंपराओं और कल्याणकारी योजनाओं की गिनती करते हुए हिमाचल ने कई मील पत्थर स्थापित किए हैं, लेकिन ये दौर खजाने पर इतने महंगे साबित हुए कि आज 75 हजार करोड़ का ऋण सारे इरादों को बांध देता है। जाहिर है कुछ फिजूलखर्चियां हुईं या सियासी तौर पर संसाधनों की बंदरबांट होती रही, जो आज आर्थिक तंगी के मुहाने तपने लगे हैं। अतः सुक्खू सरकार के हाथ अगर आगे बढऩे का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, तो प्रदेश के पांवों में भारी ऋण की बेडियां जख्म पैदा कर रही हैं। ऐसे में हिमाचल को सख्त निर्देशों के तहत तमाम संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल ही नहीं करना, बल्कि निजी निवेश की सहभागिता से विकास और प्रगति को साझा भी करना है। हिमाचल को मौजूदा अधोसंरचना का संरक्षण करते हुए ऐसा ढांचा विकसित करना है, जो रोजगार पैदा करता हुआ आर्थिकी को संबल दे। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दशकों से संसाधनों की खेती को कुछ सियासी परिंदे ही चट करते रहे, जबकि प्रदेश की समग्रता में आज भी कई तरह के असंतोष या रिसाव हैं जिन्हें भरना होगा। अगर सुक्खू सरकार पूरे प्रदेश की परिकल्पना में क्षेत्रवादी सोच को निरस्त कर पाई, तो इसके नतीजे राजनीति के प्रति जनता की सद्भावना बढ़ाएंगे। पूर्ण राज्यत्व की पूर्णता हासिल करने के लिए सरकारी कामकाज में सक्षम कार्य संस्कृति और निरंतरता चाहिए। मसलन कई अधूरी इमारतें पिछली सरकारों के दौर को भूल कर शर्मिंदा हो जाती हैं या हर बार कुछ नया करने की खोज में अतीत का खरा पक्ष छोड़ दिया जाता है। ऐसे में यह उम्मीद भी रहेगी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू उन अधूरी इमारतों को सद्गति दें, जो राजनीतिक कारणों से झूल रही हैं या जिनके ऊपर खर्च किया गया धन अनुपयोगी साबित हो रहा है। हिमाचल की प्राथमिकताओं का आधार पुनः नई कसौटियां तय कर रहा है और अगर हमें अगली मंजिलों का रास्ता मिल जाए, तो संकट कम होंगे या खोने का भय कम होगा। आर्थिक तौर पर हिमाचल को अगर संपन्न होना है तो पर्यटन, उद्योग, बागबानी, नवाचार व स्टार्टअप राज्य बनना पड़ेगा। यह सब तब होगा जब सोचने व करने का ढर्रा बदलते हुए विभागीय लक्ष्य तय होंगे। भविष्य के पाठ्यक्रम बदलने के लिए स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों का औचित्य खंगालना पड़ेगा। सरकार अगर पांच सालों में नए संस्थान खोलने के बजाय, वर्तमान को सशक्त कर दे तो सरकारी क्षेत्र में गुणवत्ता आएगी। प्रदेश में शिक्षा के लहजे को प्रमाणिकता तथा ताजगी देने के इरादे से मुख्यमंत्री ने तकनीकी ज्ञान बढ़ाने की ओर इशारा किया है। रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर वर्तमान सरकार कुछ खास करने की मंशा रखती है, लेकिन रोजगार और ज्ञान की उपलब्धियों के लिए ह्यूमैनिटीज के पाठ्यक्रम को श्रेष्ठता से जोडना होगा। प्रदेश में विज्ञान या इंजीनियरिंग कालेजों के बरअक्स कला महाविद्यालयों को उत्कृष्टता प्रदान करने की जरूरत है।

27 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

एलिजाबेथ (प्रथम) इंग्लैंड की साम्राज्ञी 1559 में बनी।
स्पेन में राष्ट्रीय दिवालिएपन की घोषणा के बाद 1607 में 'बैंक ऑफ़ जेनेवा' का पतन हुआ।
इतालवी खगोलविद, भौतिकविद एवं गणितज्ञ गैलीली गैलिलियो ने 1610 में बृहस्पति के चौथे उपग्रह कैलिस्टो की खोज की।
मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फर ने 1709 में अपने तीसरे भाई काम बख्श को हैदाराबाद में हराया।
उदयपुर के राणा ने 1818 में मेवाड़ प्रांत की रक्षा के लिये ब्रिटिश सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना के अधिकारी डॉ. विलियम ब्राइडन 1842 में 'आंग्ल अफ़गान युद्ध' में जिंदा बचे रहने वाले इकलौते ब्रिटिश सदस्य रहे।
अंग्रजों और सिखों के बीच 1849 में चिलियनवाला में दूसरा युद्ध हुआ।
असम में युवाओं ने 1889 में अपनी साहित्यिक पत्रिका 'जोनाकी का प्रकाशन शुरु किया।
न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण 1910 से प्रारम्भ हुआ।
इटली के एवेज्जानो शहर में 1915 में आये विनाशकारी भूकंप में 30 हजार से अधिक लोग मारे गए।
1930 में पहली बार मिकी माउस कॉमिक स्ट्रिप का प्रकाशन हुआ।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता बनाये रखने के लिये 1948 में आमरण अनशन शुरू किया।
टोगों के राष्ट्रपति सिलवेनस ओलिम्पियो की 1963 में एक सैनिक विद्रोह में हत्या कर दी गयी।
भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1964 में हिंदू और मुसलमानों के बीच भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। जिनमें करीब 200 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए।
1966 में अमेरिका ने नवादा में परमाणु परीक्षण किया।
नासा ने 1978 में पहली अमेरिकन महिला अंतरिक्षयात्री का चयन किया।
1988 में चीन के राष्ट्रपति चिंग चियांग कुमो का निधन।
अमरीका और उसके सहयोगियों ने 1993 में दक्षिणी इराक़ में नो फ़्लाई ज़ोन लागू करने के लिए इराक़ पर हवाई हमले की शुरूआत की।
1995 में बेलारूस नाटो का 24वाँ सदस्य देश बना।
परमाणु कार्यक्रम को लेकर 2006 में ईरान पर सैन्य आक्रमण से ब्रिटेन ने इन्कार किया।
महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 37वाँ अधिवेशन 2007 में न्यूयार्क में शुरू।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारुख़ अब्दुल्ला 2009 में नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष बनाए गए।

सरकारी संपत्तियों का ऑडिट

एक छोटी सी पहल पूरा परिदृश्य बदल सकती है, खासतौर पर अगर इसका संबंध सरकारी क्षेत्र से हो। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार उनके द्वारा विभाग की विभिन्न इमारतों के ऑडिट से न केवल बीस शहरों में 11 लाख वर्ग फुट एरिया खाली कराया जा सका, बल्कि कबाड़ का निपटारा कराकर 22 लाख रुपए भी हासिल हुए। सार्वजनिक ढांचे का सदुपयोग अब विकास की धुरी को बदलने की पहली शर्त है और इसलिए सरकारी संपत्तियों का ऑडिट जरूरी हो जाता है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में सरकारी संपत्तियों का सौ फीसदी इस्तेमाल कई मायनों में नहीं हो रहा है। इसकी एक वजह बिल्डिंग डिजाइन की खामियां हैं, जबकि भूमि का सही इस्तेमाल दूसरी सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है। पूरे प्रदेश में लैंड बैंक की अवधारणा का न होना तथा टीसीपी कानून के तहत लैंड पूलिंग की दिशा में न बढऩा भी इसके कारणों में शामिल है।

अकसर शिक्षा व चिकित्सा संस्थानों के करीब की जगह किसी अन्य विभाग को आबंटित करके इन संस्थानों के भविष्य का स्कोप रोक दिया जाता है। विभागों के तहत आबंटित कार्यालय निर्माण की जगह बेतरतीब रिहायशी भवन खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि यह भूमि आगे चलकर कार्यालय के स्तरोन्नत होने या गतिविधियां बढऩे के कारण अतिरिक्त दफ्तर निर्माण के लिए रहनी चाहिए। इस दिशा में धूमल सरकार ने संयुक्त कार्यालय परिसरों के निर्माण को बढ़ावा देकर, एक रास्ता खोजा था और इसलिए जिला स्तर पर कई स्थानों पर मिनी सचिवालय निर्मित हुए। बावजूद इसके आज भी शिमला, सोलन, मंडी व धर्मशाला में कई बड़े साहबों की कोठियों के तहत इतनी जमीन उपलब्ध है कि कई बस्तियों का निर्माण हो सकता है। इसी तरह कमोबेश हर विभाग अपने तौर पर तरह-तरह के रेस्ट हाउसों का निर्माण करता है। शिमला और धर्मशाला में ऐसे दर्जनों डाक बंगले दर्जनों एकड़ जमीन रोक कर ही नहीं पसरे, बल्कि इनके रखरखाव में भी हर साल लाखों खर्च करने पड़ते हैं। हमारा मानना है कि तमाम प्रशासनिक शहरों में जरूरत के मुताबिक एक ही स्थल पर बीस, पचास या सौ कमरों की क्षमता के संयुक्त डाक बंगलों का निर्माण करके इनका संचालन या तो पर्यटन विकास निगम करे या बेरोजगार युवाओं को इन्हें चलाने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा दो-तीन शहरों को मिलाकर कुछ विभागों के दायित्व को विस्तार देते हुए, इनके कार्यालय किसी केंद्रीय स्थल पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं।

इसी तरह दो या तीन शहरों के मध्य सरकारी आवासीय बस्तियों को कर्मचारी नगर के प्रारूप में बसाया जा सकता है। हिमाचल की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक भूमि का सदुपयोग अति आवश्यक हो जाता है। इसके लिए एक केंद्रीय एजेंसी का गठन करना होगा ताकि सार्वजनिक संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल की नीति बन सके। पूरे प्रदेश के लिए एक एस्टेट विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करके, सार्वजनिक संपत्तियों का जरूरत के अनुसार विकास, रखरखाव तथा प्रबंधन किया जाए तो न केवल संसाधनों की बचत होगी, बल्कि भविष्य का खाका भी बनेगा। हर शहर के प्रशासनिक रुतबे के अनुरूप सर्वप्रथम पहले से मौजूद संपत्तियों का ऑडिट करके, बेकार या कम इस्तेमाल हो रहे परिसर सामने आएंगे और एक प्रदेश स्तरीय विवरण भी तैयार होगा।

कोरोना की बुनियादी ड्रिल

कोरोना संक्रमण की आशंकाओं और खतरों के मद्देनजर देश भर के प्रमुख अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चिकित्सा की बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों के आकलन के लिए यह समझदारी वाला प्रयास था। हम कोरोना की दो भयावह और हत्यारी लहरों को देख और झेल चुके हैं, लिहाजा सबक हमारे सामने हैं। कुल तीन लहरें गुजऱ चुकी हैं। मॉक ड्रिल के निष्कर्ष भी कमोबेश सकारात्मक रहे। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। अस्पतालों के सघन चिकित्सा कक्षों में वेंटिलेटर भी सुचारू रूप से सक्रिय पाए गए। कोरोना के लिए जरूरी दवाओं, उपकरणों और स्टाफ की मौजूदगी भी उत्साहवर्धक रही। अब भारत पीपीई किट्स का निर्यात करता है। टेस्टिंग हमारी चिकित्सा प्रणाली की साबित बुनियाद है, जिससे वायरस की पहचान की जा सकती है। राजधानी दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान, बैंकॉक आदि देशों-शहरों से आने वाले यात्रियों की उचित जांच की जा रही है। ऐसी व्यवस्था सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर होगी! मंगलवार को दिल्ली में 13 संक्रमित यात्रियों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि यात्रियों में कोरोना संक्रमण के स्पष्ट लक्षण नहीं थे, फिर भी उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं।

हालांकि हमारे यहां टेस्टिंग का रोज़ाना औसत 1 लाख के करीब है, जबकि नवम्बर में यही औसत 2 लाख रोज़ाना से भी अधिक था। संभव है कि इसीलिए भारत में औसतन संक्रमित मरीज हररोज 200 से भी कम हैं। मंगलवार को तो यह आंकड़ा 157 ही रहा। करीब 142 करोड़ की आबादी वाले देश में संक्रमण का यह आंकड़ा नगण्य है और देश में उपचाराधीन सक्रिय मामले भी 3421 हैं। बहरहाल कुछ अपवादों के साथ मॉक ड्रिल तब की गई, जब 26 दिसंबर को भारत में कोरोना संक्रमण का औसत, प्रति 10 लाख लोगों के पीछे, मात्र 0.13 था। उसी दिन फ्रांस और जर्मनी में यही औसत क्रमशः 547.7 और 301.7 था। यूरोप और भारत में कोरोना संक्रमण की स्थितियों के बीच कितने सौ गुना के फासले हैं? इसके बावजूद मॉक ड्रिल से एक दिन पहले कर्नाटक ऐसा प्रथम राज्य बना, जिसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य घोषित किया। हालांकि इस अनिवार्यता के साथ किसी भी तरह का जुर्माना या दंड नत्थी नहीं किया गया है, हालांकि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने सतर्कता और सावधानी के आग्रह जरूर किए हैं।

हमारा मानना है कि भारत में कोरोना संक्रमण के ऐसे डरावने आसार नहीं हैं कि खासकर सेवा उद्योग क्षेत्र पर फिजूल की पाबंदियां चस्पा की जाएं, क्योंकि सेवा क्षेत्र का कारोबार हाल ही में पूर्व-कोरोना की स्थिति में पहुंचा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ी और बेहद महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की ही है। बेशक कोरोना संक्रमण पर लगाम कसे रखना हमारी बुनियादी प्राथमिकता है। मॉक ड्रिल से हमारी कमियां, आधी-अधूरी तैयारियां भी सामने आई हैं, जिन्हें समयानुसार दुरुस्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में बूस्टर अथवा प्रीकॉशन डोज को भी हमें नजऱअंदाज़ नहीं करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, भारत में प्रत्येक 100 लोगों पर बूस्टर डोज का औसत 16.16 है, जबकि वैश्विक औसत 30.23 है। यह लुंज-पुंज स्थिति टीकों की कमी के कारण नहीं है। दरअसल लोगों में जागरूकता नहीं है और कुछ पूर्वाग्रह भी हैं। बूस्टर से हम कोरोना के खिलाफ एक सशक्त लड़ाई जीत सकते हैं। मॉक ड्रिल, मास्क और अधिक टीकाकरण ऐसे सार्थक प्रयास और निर्णय हैं, जिनके माध्यम से संक्रमण पर निगरानी रखी जा सकती है और आर्थिक विकास भी पटरी पर दौड़ता रह सकता है।

पीके खुराना

खोमचे वाले, पटरी वाले, घूम-घूम कर सामान बेचने वाले इन लोगों की हम उपेक्षा करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की अधिकांश जरूरतें यही लोग पूरी करते हैं। बड़े उद्योग घाटे में जाएं तो सरकारों में हडक़ंप मच जाता है और उनके लिए राहत पैकेज की बात होने लगती है, जबकि असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं करती। हमारी अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का योगदान सिर्फ 25 प्रतिशत है, जबकि असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था में 70 प्रतिशत तक योगदान देता है। आज आवश्यकता है कि हम इस उद्योग की महत्ता को समझें

असंगठित उद्योग का महत्त्व

135 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में युवाओं की संख्या विश्व भर में सर्वाधिक है और हम इस बात पर बहुत गर्व करते प्रतीत होते हैं कि हम विश्व के सर्वाधिक युवा देश हैं। देश में युवाओं की आबादी सर्वाधिक होने के अपने लाभ हैं, लेकिन इसी कारण जो चुनौतियां दरपेश हैं उनकी चर्चा बहुत कम है। युवाओं की बड़ी आबादी का मतलब है कि छोटे से छोटे अवसर के लिए भी युवाओं की बड़ी संख्या उस अवसर का लाभ उठाने की जुगत कर रही होगी। नौकरी की तो बात ही छोड़िए, फीस देकर पढ़ाई करने वालों में भी ऐसी गलाकाट प्रतियोगिता है कि किसी अच्छे कालेज में दाखिला लेना भी एक प्रोजेक्ट हो जाता है। आज हालत यह है कि बड़े शहरों में नर्सरी क्लास में नन्हे-नन्हे बाल-गोपालों के दाखिले के लिए तगड़ी सिफारिश, रिश्वत या डोनेशन आम बात है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो हाल ही में युवाओं में फैलते नशे की आदत के कारण बदनाम हुआ जबकि इससे पहले यह कबूतरबाजी के लिए भी बदनाम रहा है। पंजाब से विदेशों में पढ़ाई के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी काफी है। विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक एक विद्यार्थी से जब मैंने इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि भारतवर्ष में उसे अपने मनचाहे कालेज में दाखिला नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने विदेश जाकर पढ़ाई करने का निश्चय किया है। जिस देश में नर्सरी क्लास में दाखिले के लिए रिश्वत देनी पड़े, वहां युवकों को नौकरी के कैसे लाले होंगे यह अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। यही कारण है कि बैंकों में चपरासी तथा रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षित युवकों में भी होड़ लगी रहती है। सिर्फ एक साल पहले ही यह खबर बहुत चर्चा का विषय बनी थी कि राजस्थान में एक विधायक के उच्च शिक्षित बेटे को चपरासी की नौकरी के लिए चुना गया है। समस्या यह है कि हमारे देश में यह धारणा आम है कि नौकरी देना सरकार का कत्र्तव्य है। यह समझना आवश्यक है कि सरकारी नौकरियां न केवल सीमित हैं, बल्कि वे हमेशा सीमित ही रहेंगी। सरकार का काम नौकरी देना नहीं है। सरकार का काम है कि वह ऐसे नियम-कानून बनाए कि उद्योग फल-फूल सकें और अधिक से अधिक रोजगार पैदा कर सकें। समस्या यह है कि यह धारणा सिर्फ जनता में ही नहीं है बल्कि राजनीतिज्ञों में भी आम है कि नौकरी देना सरकार का कत्र्तव्य है। यही कारण है कि सरकारें बार-बार नई नौकरियां देने की घोषणाएं करती हैं और फिर अपनी ही घोषणाओं के जाल में फंस कर जोड़-तोड़ से नौकरियां बनाने के चक्रव्यूह में उलझ जाती हैं। इसी तरह की एक दूसरी गलतफहमी यह है कि बड़े उद्योग लगने से रोजग़ार के अवसरों में वृद्धि होगी। तकनीक में तेजी से उन्नति के लिए हमें विश्व भर में फैले वैज्ञानिकों का आभारी होना चाहिए, लेकिन तकनीकी उन्नति ने जहां हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं बड़े उद्योगों में मशीनों, कंप्यूटरों और रोबोट का दखल बढ़ते जाने से इनसानों के लिए रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। यह सही है कि आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के चलते उद्योगों का विकास हुआ है, लेकिन इससे रोजग़ार के अवसर संकुचित हुए हैं। एक और बड़ी गड़बड़ यह है कि रोजग़ार कार्यालयों में दर्ज बेरोजग़ारों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कम पढ़े-लिखे तो हैं ही, उनमें कोई तकनीकी योग्यता भी नहीं है।

इस कारण उन्हें या तो नौकरी मिलती ही नहीं, और अगर मिलती भी है तो तनख्वाह चिडिया के चुग्गे जैसी होती है। उन्हें रोजग़ार के काबिल बनाना एक बड़ी चुनौती है और इसके बिना मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी सभी घोषणाएं कागज़ी बन कर रह जाती हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ श्रम शक्ति का एक बहुत छोटा भाग ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। सच तो यह है कि हमारी बहुसंख्य श्रमशक्ति कृषि, बागवानी तथा अन्य छोटे-छोटे काम धंधों में संलग्न है। आकार के कारण अक्सर हम बड़े रोजग़ारों के प्रति विस्मय, आदर और डर की मिलीजुली भावना से ग्रस्त रहते हैं, जबकि असलियत यह है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र के योगदान के कारण ही ज़िंदा है, वरना हम बहुत पहले ही पाकिस्तान की तरह मदद के लिए फरियाद कर रहे होते। इस तथाकथित असंगठित क्षेत्र के बारे में और भी ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिनकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते और असंगठित क्षेत्र की अनदेखी की गलती करते हैं। असंगठित क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां उद्यमिता खुल कर पनपती है। असंगठित क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े और दिव्यांग तक को रोजग़ार हासिल है जबकि संगठित क्षेत्र की बहुत सी सीमाएं हैं। असंगठित क्षेत्र में ठेला लगाने वाले बहुत से लोग मौसम बदल जाने पर प्रोडक्ट बदल देते हैं।

इनसाइड

केवाईसी के बिना नहीं खरीद सकेंगे बीमा, पुराने पॉलिसीधारकों पर भी होगा लागू

नई दिल्ली। अभी किसी भी गैर-जीवन या सामान्य बीमा जैसे स्वास्थ्य, वाहन या फिर यात्रा बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, अगर किसी स्वास्थ्य बीमा के संबंध में क्लेम (दावा) एक लाख रुपये से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में पॉलिसीधारकों के लिए पैन और आधार कार्ड देना जरूरी होता है। नए साल से किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी (ग्राहक को जानिये) देना जरूरी होगा। इसके बिना ग्राहक कोई भी पॉलिसी नहीं खरीद सकेंगे। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि एक जनवरी से जीवन बीमा, वाहन और स्वास्थ्य समेत सभी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहकों को केवाईसी देना जरूरी होगा।

अभी किसी भी गैर-जीवन या सामान्य बीमा जैसे स्वास्थ्य, वाहन या फिर यात्रा बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, अगर किसी स्वास्थ्य बीमा के संबंध में क्लेम (दावा) एक लाख रुपये से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में पॉलिसीधारकों के लिए पैन और आधार कार्ड देना जरूरी होता है।

इरडा के फैसले का मतलब कि क्लेम से पहले अब पॉलिसी खरीदते समय ही केवाईसी का नियम लागू होगा। यह नियम उन पर भी लागू होगा, जिनके पास पहले से पॉलिसी है। अगर कम जोखिम वाली पॉलिसी है तो पॉलिसीधारक के लिए दो साल के भीतर केवाईसी पूरा करना होगा। अन्य ग्राहकों व ज्यादा जोखिम वाली पॉलिसियों के ग्राहकों के लिए एक साल का समय दिया गया है। इसके लिए बीमा कंपनी को संदेश और ईमेल से जानकारी देनी होगी।

नवीनीकरण के लिए भी केवाईसी जरूरी

इस नियम के मुताबिक, अगर आपकी पॉलिसी का नवीनीकरण एक जनवरी, 2023 के बाद होना है तो आपको केवाईसी करानी होगी। इसके लिए फोटो पहचान पत्र और पता (एड्रेस) संबंधी दस्तावेज बीमा कंपनी के पास जमा कराना होगा। अगर आप केवाईसी नहीं देते हैं तो न तो आप नई पॉलिसी खरीद पाएंगे और न ही नवीनीकरण करा पाएंगे।

50,000 से ज्यादा प्रीमियम पर देना होता है पैन कार्ड

अभी ऐसे पॉलिसीधारकों को पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा कराना होता है, जिनका किसी एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये या इससे ज्यादा प्रीमियम होता है। जानकारों का कहना है कि इस नए दिशा निर्देश से दावों का फटाफट निपटान होगा। इससे ग्राहकों को फायदा होगा। साथ ही किसी तरह की धोखाधड़ी से भी बचने में मदद मिलेगी। दावों के समय पॉलिसीधारकों को किसी भी केवाईसी को देने की जरूरत नहीं होगी। बीमा कंपनियों के लिए यह राहत होगी कि वे कभी भी ग्राहकों की अलग-अलग पॉलिसी से जुड़े इतिहास को देख सकेंगे।

बजट 2023-24: हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हुई बजट की उल्टी गिनती, हफ्तेभर बंद रहेंगे वित्त मंत्रालय के कर्मचारी

एनटीवी न्यूज

पारंपरिक हलवा सेरेमनी के साथ ही बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। उससे पहले गुरुवार को सीतारमण की मौजूदगी में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। कोरोना के कारण पिछले दो साल इसका आयोजन नहीं हो पाया था। हलवा सेरेमनी बजट की तैयारी पूरी होने का संकेत होती है। इसके साथ ही बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी 14 यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स यूनियन बजट मोबाइल एप पर उपलब्ध होंगे।

नई दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। गुरुवार को परंपरागत हलवा सेरेमनी के साथ बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नॉर्थ ब्लॉक में सीतारमण की मौजूदगी में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड और पंकज चौधरी तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हर साल बजट की तैयारी के लिए लॉक इन प्रोसेस (lock-in process) से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस सेरेमनी के दौरान वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया।

क्यों मनाई जाती है यह सेरेमनी

बजट डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग शुरू होने के साथ ही पारंपरिक हलवा सेरेमनी मनाई गई। इस बार हलवा सेरेमनी गणतंत्र दिवस के दिन हुई। बजट को अंतिम रूप देने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में हलवा बनाया जाता है। यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इसकी वजह यह है कि अपने यहां हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से होती है। कोरोना महामारी के कारण पिछले दो साल हलवा सेरेमनी नहीं हो पाई थी। इसकी जगह कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिठाई दी गई थी।

क्या है हलवा सेरेमनी

हलवा सेरेमनी बजट की तैयारी पूरी होने का संकेत होती है। दशकों से बजट से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन होता आया है। इसे बजट के दस्तावेजीकरण के बाद मनाया जाता है। नार्थ ब्लॉक में जहां वित्त मंत्रालय है, उसके नीचे बेसमेंट में बजट प्रेस है। इस बजट प्रेस में हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है। हलवा सेरेमनी के बाद बजट के छपाई शुरू होती है। हलवा सेरेमनी के बाद बजट निर्माण में लगे सभी कर्मचारी इस बेसमेंट में ही रहते हैं।

बेसमेंट में रहते हैं कर्मचारी

इस सेरेमनी में सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में एक बड़ी कढ़ाही में हलवा बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी कई दिनों से बजट निर्माण में लगे होते हैं। बजट बनने पर उनकी मेहनत को सराहा जाता है। इसके लिए हलवा खिलाकर उनका मुंह मीठा किया जाता है। हलवा सेरेमनी के बाद वित्त मंत्रालय के कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं। ये कर्मचारी वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद ही बाहर निकलते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जिससे बजट से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक ना होने पाए।

कौन होते हैं ये कर्मचारी

ये वो कर्मचारी हैं जो बजट के बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं और इन्हें एक तरह से नजरबंद रखा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश करने के बाद ही ये अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के संपर्क में आते हैं। इसका मकसद बजट को गोपनीय रखना होता है। बजट छापने के लिए नॉर्थ ब्लॉक के अंदर ही प्रेस भी स्थित है।

डिजिटल बजट

पिछली दो बार की तरह इस बार भी बजट पेपरलेस होगा। सभी 14 यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स यूनियन बजट एक फरवरी को बजट पेश होने के बाद मोबाइल एप पर उपलब्ध होंगे। इनमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, फाइनेंस बिल आदि शामिल होते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट कहा जाता है। यह एप एंड्रॉयड और एप्पल ओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

बिक रहे नकली हॉलमार्क वाले गहने, नुकसान से बचाने के लिए नियम सख्त

नई दिल्ली। कुछ समय पहले ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) ने सभी तरह की सोने की जूलरी पर हॉलमार्किंग जरूरी किया था। उसके बाद पूरे देश में नकली हॉलमार्क का चलन तेजी से बढ़ गया है। सूत्रों ने कहा कि जूलरी निर्माता तस्करी वाला सोना खरीदते हैं। उसी पर अवैध तरीके से हॉलमार्किंग कर खुदरा बाजार में बेच रहे हैं।

देश भर में ग्राहकों को नकली हॉलमार्क वाले सोने के गहने बेचे जा रहे हैं। बड़े जूलरी कारोबारी और उद्योग के लोगों ने सरकार से कहा है कि इस नकली हॉलमार्क के बाजार को खत्म करने के लिए कोई ठोस नियम लाया जाए। कुछ समय पहले ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) ने सभी तरह की सोने की जूलरी पर हॉलमार्किंग जरूरी किया था। उसके बाद पूरे देश में नकली हॉलमार्क का चलन तेजी से बढ़ गया है। सूत्रों ने कहा कि जूलरी निर्माता तस्करी वाला सोना खरीदते हैं। उसी पर अवैध तरीके से हॉलमार्किंग कर खुदरा बाजार में बेच रहे हैं। इस तरह के सोने प्रति ग्राम 200-300 रुपये सस्ते में बेचे जाते हैं। इससे ग्राहक इनकी ओर ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, जबकि कारोबारियों को नुकसान हो रहा है।

तस्करी व आयात के संबंधों का लगाएं पता: वित्त मंत्री

इसी महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अधिकारियों को यह पता लगाना चाहिए कि क्या सोने के ज्यादा आयात और तस्करी के बीच कोई संबंध है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अनुसार, 2021-22 में 500 करोड़ का 833 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त हुआ था। 2020-21 में खाड़ी क्षेत्र से तस्करी में गिरावट देखी गई थी।

भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक को डेनमार्क को सौंपेगा दुबई, टैक्स धोखाधड़ी का है मामला

नई दिल्ली। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि 1.7 अरब डॉलर की कर धोखाधड़ी मामले के मास्टरमाइंड 52 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक को डेनमार्क प्रत्यर्पित किया जाए। गुरुवार को यहां जारी एक बयान के अनुसार, यह फैसला दुबई के अटॉर्नी जनरल चांसलर एसाम इस्सा अल हुमैदान की ओर से दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन में दायर अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया गया।

दुबई की एक अदालत ने 1.7 अरब डॉलर की कर धोखाधड़ी मामले में ब्रिटिश नागरिक को डेनमार्क प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि 1.7 अरब डॉलर की कर धोखाधड़ी मामले के मास्टरमाइंड 52 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक को डेनमार्क प्रत्यर्पित किया जाए।

हेज फंड कारोबारी संजय शाह पर 2012 से 2015 तक चलने वाली एक योजना बनाने का आरोप है, जिसमें विदेशी व्यवसायों ने डेनिश कंपनियों में शेयर होने का दिखावा किया और कर रिफंड का दावा किया। हालांकि इसके लिए वे पात्र नहीं थे।

गुरुवार को यहां जारी एक बयान के अनुसार, यह फैसला दुबई के अटॉर्नी जनरल चांसलर एसाम इस्सा अल हुमैदान की ओर से दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन में दायर अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया गया।

कोर्ट ऑफ कैसेशन ने एक अलग न्यायिक निकाय की ओर से पुनर्विचार के लिए मामले को कोर्ट ऑफ अपील को वापस करने का फैसला किया गया। इस अदालत ने शाह को डेनमार्क के अधिकारियों को प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाया।

बयान में कहा गया है, "दुबई लोक अभियोजन ने संजय शाह के खिलाफ डेनमार्क के अधिकारियों की ओर से सौंपे गए सभी दस्तावेज अदालत को सौंपे। इन दस्तावेजों से धोखाधड़ी और धनशोधन में आरोपित की संलिप्तता का पता चलता है।

दुबई पुलिस ने डेनमार्क के अधिकारियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद इस साल की शुरुआत में शाह को गिरफ्तार किया था। शाह के वकील अली अल जारूनी ने कहा कि उनके मुवक्किल दुबई कोर्ट ऑफ अपील की ओर से दिए गए प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

सितंबर में दुबई में डेनमार्क सरकार की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था कि शाह को डेनमार्क राज्य को 1.25 अरब डॉलर का भुगतान करना होगा।

बयान में कहा गया है कि आरोपित की गिरफ्तारी और फैसला धनशोधन सहित अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने की दुबई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूएई मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है, अंतरराष्ट्रीय मानकों और नीतियों को पूरी तरह से लागू करना चाहता है।

हरे निशान पर खुले घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 195 अंक चढ़ा, निफ्टी 18250 के पार

नई दिल्ली। शुक्रवार को सेंसेक्स 195 अंकों की तेजी के साथ 61329 के स्तर पर और निफ्टी 68 अंकों की तेजी के साथ 18259 के लेवल पर ओपन हुआ। वहीं, बैंक निफ्टी में150 अंकों की तेजी के साथ 43401 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत हुई।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक शुरुआत हुई है। शुक्रवार की सुबह बाजार खुलते समय सेंसेक्स में लगभग 200 अंकों की बढ़त दिखी। फिलहाल सेंसेक्स 103.99 अंकों की बढ़त के साथ 61237.87 अंकों पर जबकि निफ्टी 41.60 अंकों की बढ़त के साथ 18232.60 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है। इस दौरान रुपया 0.02% बढ़कर 82.7800 प्रति अमेरिकी डॉलर पर खुला। इसे पिछले ट्रेडिंग सेशन में यह करीब 82.7975 स्तर पर बंद हुआ था।

शुक्रवार को सेंसेक्स 195 अंकों की तेजी के साथ 61329 के स्तर पर और निफ्टी 68 अंकों की तेजी के साथ 18259 के लेवल पर ओपन हुआ। वहीं, बैंक निफ्टी में150 अंकों की तेजी के साथ 43401 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत हुई। शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में मीडिया, मेटल्स और PSU बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में तेजी दिख रही है। बजाज ट्विन्स के शेयरों में भी मजबूती दिख रही है। बजाज फाइनेंस में 2.3 फीसदी और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.2 फीसदी की तेजी है। इसके अलावा टाटा स्टील, SBI, विप्रो जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी है। जबकि एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा जैसे शेयर कमजोरी के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं।

आकाश संभालेंगे दूरसंचार, ईशा को खुदरा व अनंत को ऊर्जा कारोबार

नई दिल्ली। 104 अरब डॉलर का समूह चलाने वाले अंबानी ने कहा कि अब से पांच साल बाद रिलायंस की स्थापना को 50 साल पूरे हो जाएंगे।

अरबपति मुकेश अंबानी ने अपने तीनों बच्चों आकाश, ईशा एवं अनंत के लिए लक्ष्य तय किए हैं, जिन्हें वह दूरसंचार, खुदरा व नवीन ऊर्जा कारोबार की जिम्मेदारी सौंपेंगे।

धीरूभाई अंबानी की जयंती पर रिलायंस फैमिली डे के मौके पर उन्होंने कहा कि तेल से लेकर दूरसंचार और खुदरा तक का कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज आत्म परिवर्तन की विस्तृत यात्रा पर चल पड़ी है। 104 अरब डॉलर का समूह चलाने वाले अंबानी ने कहा कि अब से पांच साल बाद रिलायंस की स्थापना को 50 साल पूरे हो जाएंगे।

दूरसंचार : आकाश की अगुवाई में सर्वश्रेष्ठ 5जी नेटवर्क शुरू

अंबानी ने कहा, आकाश की अगुवाई में जियो देशभर में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 5जी नेटवर्क शुरू कर रही है। इस सेवा की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। लेकिन, जियो मंचों को भारत के भावी अवसरों के लिए तैयार होना चाहिए। ये अवसर हैं...घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए अनूठे डिजिटल उत्पाद एवं समाधान उपलब्ध कराना।

खुदरा : ईशा के नेतृत्व में तेजी से बढ़ा कारोबार

उद्योगपति ने कहा, ईशा अंबानी के नेतृत्व में खुदरा कारोबार तेजी से बढ़ा है। जियो की तरह खुदरा कारोबार की वृद्धि का भारत के समावेशी विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अधिक रोजगार पैदा होंगे। किसानों को उच्च आय मिलेगी। एसएमई और बड़े निर्माताओं को अधिक उत्पादक बनाने के साथ व्यापारियों को समृद्ध बनने में मदद करेंगे।

नवीन ऊर्जा : अनंत की देखरेख में बनेंगे हरित कॉरपोरेट समूह

नवीन ऊर्जा पर अंबानी ने कहा, यह रिलायंस का सबसे नया स्टार्टअप कारोबार है। इसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। अनंत इस अगली पीढ़ी के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमने जामनगर में अपने बड़े (गीगा) कारखाने तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उन्होंने कहा, रिलायंस भारत का सबसे 'हरित' कॉरपोरेट समूह भी बनने जा रहा है।

मेसी के जरिये नेतृत्व-टीमवर्क की सीख

मुकेश अंबानी ने नेतृत्व और टीमवर्क के साथ काम करने के लिए अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी की मिसाल दी। कहा, अर्जेंटीना ने कप कैसे जीता? यह नेतृत्व और टीमवर्क का मेल है। मेसी अकेले अपने दम पर कप नहीं जीत सकते थे। इसी तरह, अर्जेंटीना भी मेसी के प्रेरणादायी नेतृत्व के बिना नहीं जीत सकता था।

2047 तक 40 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी

रिलायंस प्रमुख ने भरोसा जताया कि भारत 2047 तक 40 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। हम स्थिर तरीके से इस स्थायी लक्ष्य को पा सकेंगे। उन्होंने कहा, हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी के तौर पर देख रहा है। दुनिया की निगाहें हम पर हैं।

गणतंत्र दिवस परेड इस बार क्यों खास और अलग, इन तस्वीरों को देखिए समझ आ जाएगा

एनटीवी न्यूज

पूरे देश ने 74 वें गणतंत्र दिवस मनाया। कर्तव्य पथ पर परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस बार परेड में कई ऐसी चीजें देखने को मिली जो पहली बार शामिल थीं। परेड देखने के लिए 'श्रमयोगियों' को खास जगह दी गई साथ ही इस बार मेड इन इंडिया पर पूरा जोर था।

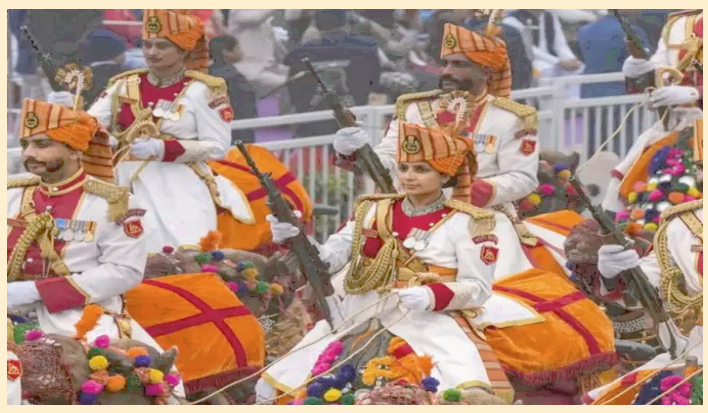

परेड में पहली बार BSF की महिला टुकड़ी ऊंट पर गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर इस साल अनोखा नजारा देखने को मिला।

गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सैन्य उपकरणों में मेड इन इंडिया की प्रमुखता रही और यह आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप थी। परेड में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, नाग मिसाइल प्रणाली, के-9 बज्र प्रणाली का प्रदर्शन किया गया।

देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य रूप से नारी शक्ति के विभिन्न रूपों के दर्शन हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य नेताओं एवं गणमान्य लोगों ने भव्य परेड देखी।

इस साल औपचारिक 21-तोपों की सलामी 105 मिमी भारतीय फील्ड गन के साथ दी गई थी, जिसने विंटेज 25-पाउंडर बंदूकों की जगह ली है।

अग्निवीर परेड में शामिल : 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देशभक्ति के जोश के बीच कर्तव्यपथ पर परेड के दौरान अग्निवीर भी शामिल हुए।

श्रमयोगियों को विशेष तौर पर किया गया आमंत्रित
सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ, नए संसद भवन के निर्माण में शामिल श्रमयोगियों का एक समूह जिसमें दूध और सब्जी विक्रेता आदि को विशेष रूप से परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया था।

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। मिस्र के शस्त्र बलों की टुकड़ी भी परेड में शामिल हुई। कर्नल महमूद मोहम्मद अब्दुल फतह अलखरसावी ने मिस्र की टुकड़ी का नेतृत्व किया।

इनसाइड

नेताओं को माला पहनाने में समय बर्बाद न करें, 2024 की तैयारी में लग जाएं- भूपेंद्र चौधरी ने दिया चुनावी मंत्र

यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अयोध्या और बस्ती जिलों के दौरे पर थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मंत्री हो या बूथ स्तर का कार्यकर्ता सभी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं।

अयोध्या: यूपी में बीजेपी की चुनावी मुहिम तेज करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Chaudhary) ने बुधवार को अयोध्या (Ayodhya News) व बस्ती जिलों का दौरा किया। उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनमें चुनावी मंत्र फूंका। अयोध्या के साहब गंज स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि अभी से मंत्री, एमपी, एमएलए से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत व लगन से जुट जाएं। उन्होंने आगे कहा, 'हमारा लक्ष्य है यूपी की सभी सीटों को जीत कर पीएम मोदी की झोली में डालना। उन्होंने कहा कि एमएलसी की पांच सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इसमें तीन स्नातक व दो शिक्षक क्षेत्र की सीटें हैं। बीजेपी को सभी सीटों पर सफलता मिले इसके लिए पार्टी कैडर के लोग सभी मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों/कार्यक्रमों की सूचना देकर पार्टी उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगें। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग अपना समय पार्टी के नेताओं के स्वागत करने में खराब न करके चुनाव की तैयारी में लगाएं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को लेकर संकल्प लिया है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नही जाएगा।

राम चरित मानस पर बैन लगाने के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही ऐसा बयान दे सकता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस पर सफाई देनी चाहिए कि यह सपा का बयान है या स्वामी का व्यक्तिगत बयान। अगर उनका बयान निजी है तो अखिलेश यादव को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

आजाद भारत के इतिहास में वो 3 वित्त मंत्री जो नहीं पेश कर सके आम बजट

एनटीवी संवाददाता

सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है। उन्होंने 10 बजट पेश किए। हालांकि, आजाद भारत के इतिहास में ऐसे भी वित्त मंत्री हुए जिन्हें बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करने वाली हैं तो आइए यहां उनके बारे में जानते हैं जो वित्त मंत्री तो बने लेकिन यह मौका पाने से चूक गए।

नई दिल्ली: बजट 2023 की उलटी गिनती शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को इसे पेश करेंगी। हर किसी को इसका बेसब्री से इंतजार है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इसमें कई लोकलुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। यह सीतारमण का चौथा बजट होगा। सबसे ज्यादा 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। हालांकि, आजाद भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो वित्त मंत्री तो बने, लेकिन बजट पेश नहीं कर सके। इसका एक कारण छोटा कार्यकाल था या फिर उनकी जगह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बजट पेश कर दिया। इनमें क्षितिज चंद्र नियोगी, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी का नाम शामिल है।

नियोगी देश के दूसरे वित्त मंत्री थे। उन्होंने आरके शणमुखम शेट्टी की जगह ली थी। यह और बात है कि नियोगी ने सिर्फ 35 दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उनके पास बजट पेश करने का मौका आया ही नहीं। वह पहले वित्त आयोग के चेयरमैन थे। 1888 में जन्मे नियोगी संविधान सभा के भी सदस्य थे। वह नेहरू की पहली कैबिनेट के सदस्य भी थे। 1948 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था।

हेमवती नंदन बहुगुणा को भी नहीं मिला बजट पेश करने का मौका

हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम भी उन वित्त मंत्रियों में शामिल है जो वित्त मंत्री तो बने लेकिन यूनियन बजट पेश नहीं किया। इस बार भी छोटा कार्यकाल कारण रहा। बहुगुणा 1979 में तत्कालीन इंदिरा सरकार में साढ़े पांच महीने की अवधि के लिए वित्त मंत्री बने थे। इस अवधि में बजट नहीं पड़ा। वह बिना बजट पेश किए ही पद से हट गए थे। हेमवती नंदन बहुगुणा दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।

नारायण दत्त तिवारी की जगह राजीव ने पेश किया था बजट

वित्त मंत्री बनने के बावजूद आम बजट न पेश कर पाने वालों की लिस्ट में नारायण दत्त तिवारी का भी नाम आता है। एनडी तिवारी अपने जमाने के दिग्गज नेता थे। तीन बार वह उत्तर प्रदेश के सीएम बने। वह उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। तिवारी आंध्रप्रदेश के राज्यपाल भी रहे। 1987-88 में नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री बने थे। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस समय नारायण दत्त तिवारी की जगह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया था।

देश की पहली कोरोना नेजल वैक्सीन लॉन्च, जानिए- कितनी है कीमत

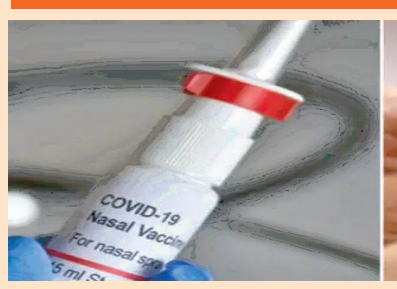

नेजल वैक्सीन को लगाने के लिए सुई का प्रयोग नहीं होता और इसे नाक के जरिये दिया जाएगा। सबसे पहले इससे इंजेक्शन का डर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इंजेक्शन लेने वाली जगह पर दर्द, चुभन आदि वाले एडवर्स इफेक्ट्स का खतरा भी कम हो जाएगा। इसके साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज होगी।

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत बायोटेक के नेजल कोविड टीके इनकोवैक को लांच किया। नाक के जरिये दिये जा सकने वाले दुनिया के पहले भारत निर्मित टीके को यहां मांडविया के आवास पर लांच किया गया। नेजल टीके बीबीवी154 को हीट्रोलोगस बूस्टर खुराक के रूप में वयस्कों में सीमित उपयोग के लिए नवंबर में भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की मंजूरी मिली थी।

भारत बायोटेक के पहले जारी एक बयान के अनुसार इनकोवैक की कीमत निजी क्षेत्र के लिए 800 रुपये और भारत सरकार और राज्य सरकारों को आपूर्ति के लिए 325 रुपये है। हीट्रोलोगस बूस्टर खुराक में प्राथमिक खुराक से अलग बूस्टर खुराक दी जा सकती है। हैदराबाद से संचालित कंपनी ने एक बयान में कहा था कि तीन चरणों में क्लीनिकल परीक्षणों में इस टीके के सफल परिणाम आये।

खास बात है कि इस वैक्सीन को वैक्सीन को डिलीवर करना और बनाना मस्कुलर वैक्सीन की तुलना में ज्यादा आसान है। नेजल वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्टोर करके रखा जा सकता है। वैक्सीन गेमचेंजर साबित हो सकती है। इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार में और अधिक तेजी आएगी।

दिल्ली में हैं 15 साल पुरानी 50 लाख से अधिक गाड़ियां, जानें कौन राज्य है टॉप पर

रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा पिछले हफ्ते संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पूरे देश में रजिस्टर्ड कम से कम 4 करोड़ गाड़ियां 15 साल से अधिक पुरानी हैं। इनमें से आधी गाड़ियां 20 साल से अधिक पुरानी हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में 50 लाख से अधिक रजिस्टर्ड गाड़ियां 15 साल से अधिक पुरानी हैं। पूरे देश में 15 साल से पुरानी गाड़ियों के मामले में दिल्ली का तीसरा नंबर है। इनमें से 70 फीसदी 20 साल से ज्यादा पुरानी हैं। इस लिस्ट में कर्नाटक टॉप पर है। राज्य में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की संख्या करीब 70.1 लाख है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां 56.5 लाख गाड़िया 15 साल से अधिक पुरानी हैं।

रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा पिछले हफ्ते संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पूरे देश में रजिस्टर्ड कम से कम 4 करोड़ गाड़ियां 15 साल से अधिक पुरानी हैं। इनमें से आधी गाड़ियां 20 साल से अधिक पुरानी हैं। असल में इन वाहनों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। ये आंकड़े वाहन 4 के सेंट्रल वीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के डिजिटाइज्ड वीकल डेटा से लिए गए हैं। इसमें तीन बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए तो..

ये आंकड़े इसलिए अहम हैं क्योंकि सरकार ने 1 जून, 2024 से फिटनेस टेस्ट में नाकाम होने वाले 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने पर्सनल वीकल्स को अनिवार्य रूप से डी-रजिस्टर कर दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि अभी गाड़ियों को डी-रजिस्टर्ड करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए बड़ी संख्या ऐसी गाड़ियों की हो सकती है जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन जो अब भी रजिस्टर्ड वीकल्स की कैटगरी में हैं।

लोगों को पुरानी गाड़ियां रखने से हतोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह के उपाय कर रही हैं। इनमें ग्रीन टैक्स भी शामिल है। आठ वर्ष से पुराने सभी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा। यह रोड टैक्स का 10-25 फीसदी हो सकता है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई अहम बदलावों के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जाएगी। प्रस्ताव को राज्यों के पास भेजा गया है।

भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल नहीं होगी जेडीयू! ललन सिंह बोले- विपक्ष को एकजुट करे कांग्रेस

जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि वे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। ललन सिंह के अनुसार, नागालैंड में राजनीतिक कार्यक्रम होने के कारण वे समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। बता दें कि 30 जनवरी को श्रीनगर में समापन समारोह होगा।

पटना: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के समापन कार्यक्रम में 30 जनवरी को श्रीनगर में शामिल होने से बृहस्पतिवार को असमर्थता जताई है। ललन सिंह ने कांग्रेस से विपक्ष को एकजुट करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे एक पत्र में जेडीयू अध्यक्ष ने यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए चुनावी राज्य नगालैंड में अपना एक राजनीतिक कार्यक्रम होने का उल्लेख किया। दरअसल, कांग्रेस ने कई गैर-भाजपा दलों के प्रमुखों को यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कुछ क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों द्वारा अपने संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर अन्य नेताओं को भेजे जाने की संभावना है। गौरतलब है कि इस समय विपक्ष इस बात को लेकर खुद विभाजित है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ इस तरह के किसी गठबंधन को क्या आकार दिया जाना चाहिए और इसका नेतृत्व किसे करना चाहिए।